● वर्ष-3
● अंक-186
रायपुर, बुधवार
13 मार्च 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› पश्चिम दिशा में बेडरूम होने पर...

**● कृषक उन्नति योजना मुख्यमंत्री ने बालोद से किया शुभारंभ ● प्रधानमंत्री मोदी की किसानों से की गई एक और गारंटी हुई पूरीः मुख्यमंत्री**

## 24.72 लाख किसानों के बैंक खाते में 13 हजार 320 करोड़ का हुआ अंतरण

# छग किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य

**रायपुर।** कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए का दिन सदैव अविस्मरणीय रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ जिला मुख्यालय बालोद स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हजारों किसानों एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के हाथों हुआ। उन्होंने इस कार्यक्रम में राज्य के 24 लाख 72 हजार किसानों को योजना के तहत 13 हजार 320 करोड़ रूपए की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव राजनांदगांव में आयोजित समारोह में शामिल हुए और बालोद

में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को भी उन्होंने सम्बोधित किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज वह शुभ दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के बैंक खातों में 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि का अंतरण किया जा रहा है। कार्यक्रम में 24 लाख 75 हजार से अधिक किसानों के खातों में राशि भेजी जा रही है। इनमें से 24 लाख 72 हजार वे किसान हैं, जिन्होंने इस साल धान बेचा था। उन्हें 13 हजार 289 करोड़ रुपए के अंतर की राशि का भुगतान किया गया है। इसी तरह 02 हजार 829 धान बीज उत्पादक किसानों को भी बीज निगम के माध्यम से अंतर राशि, 31 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअली जुड़ने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को धन्यवाद दिया। साय ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान भाइयों से किए गए वादे के अनुरूप अटल जी के जन्मदिन, सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल के बकाया धान बोनस 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किसान भाइयों के खातों में कर दिया है। 13 लाख से ज्यादा किसानों को बोनस का लाभ मिला है।

मोदी जी ने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर गरीबों के लिए 18 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमने कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय ले लिया है, अप्रैल माह से तीव्र गति से मकान बनने शुरू होंगे।

मोदी जी ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना शुरू करने की गारंटी दी थी। यह योजना भी शुरू हो चुकी है। परसों 10 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से राज्य की 70 लाख से अधिक माताओं और बहनों के बैंक खातों में 655 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है।

श्री साय ने कहा की मोदी जी ने वनवासी भाइयों से वादा किया था कि तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए कर देंगे। आज से ही इस योजना की भी शुरूआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने जो दायित्व सौंपे हैं। उन्हें हम हर हाल में पूरा करेंगे।

### छत्तीसगढ़ में किसानों के घर हो रही धन वर्षाः यादव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ऐसा लग रहा है आज मानों छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारन्टी आज पूरी हुई। किसानों को आदान सहायता देने में छत्तीसगढ़ में जो कार्य हुआ है वह किसी अन्य राज्य में नहीं किया गया है। डॉ. यादव आज राजनांदगांव जिले में कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण और किसान मेला को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सांसद श्री संतोष पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजनांदगांव से वर्चुअल रूप से जुड़कर मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में बालोद में आयोजित राज्य स्तरीय कृषक उन्नति योजना के कार्यक्रम को भी सम्बोधित किया।

## कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची

**नई दिल्ली।** कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 12 मार्च को 43 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है। केसी वेणुगोपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में

उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस मौके पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी है। आज, हम दूसरी सूची की घोषणा करने जा रहे हैं। कल सीईसी ने बैठक की और असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लगभग 43 नामों की सूची को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। नकुलनाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। राहुल कस्वा राजस्थान के चुरू से चुनाव लड़ेंगे। वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची में 43 उम्मीदवारों में से 10 जनरल उम्मीदवार, 13 ओबीसी उम्मीदवार, 10 एससी उम्मीदवार, 9 एसटी उम्मीदवार और 1 मुस्लिम उम्मीदवार हैं।

## जीत दिलाने की क्षमता ही प्राथमिकता, मुख्यमंत्री चेहरे में बदलाव के साथ भाजपा का स्पष्ट संदेश

**नई दिल्ली।** जब दरी पर सोने का जमाना था, तब भी हम साथ थे। उस समय इनके (खट्टर के) पास एक मोटरसाइकिल थी। हमलोग उसी पर सवार होकर हरियाणा भ्रमण करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि खट्टर मोटरसाइकिल चलाते थे और वह पीछे बैठा करते थे। रोहतक से निकलते थे और गुरुग्राम आकर रुकते थे। गुरुग्राम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए मनोहर लाल खट्टर की प्रगतिशील मानसिकता के बारे में खुलकर बात की थी, साथ ही उन अच्छे पुराने दिनों को याद किया था। 2014 में मुख्यमंत्री पद के लिए सरल स्वभाव वाले खट्टर एक अप्रत्याशित पसंद थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 47 सीटें जीतकर आश्चर्यचकित कर दिया, जो 2009 में दो सीटों से एक बड़ी

छलांग थी। सीएम खट्टर ने लिए आगे चुनौतियां अपार थी। उनके लिए राज्य से संबंधित सभी जानकारी उनकी उंगलियों पर थी। अंतिम क्षण तक जब खट्टर ने सैनी का नाम प्रस्तावित किया, सीएमओ का एक वर्ग मीडियाकर्मियों को आश्वस्त करता रहा कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं।

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के साथ उसके गठबंधन में दरारें पिछले साल 10 लोकसभा सीटों के लिए संघर्ष के बीच दिखाई देने लगी थीं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि भाजपा उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी भी इसी तरह का दावा कर रही थी। यह किसी से छिपा नहीं था कि यह आपसी सुविधा का गठबंधन था, साझा विचारधारा का नहीं। जेजेपी का जन्म 2019 के विधानसभा चुनावों से पहले इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) में ऊर्ध्वाधर विभाजन के परिणामस्वरूप हुआ था। उसने 10 विधानसभा सीटें जीतकर खुद को किंगमेकर की भूमिका में पाया। जिस सदन में भाजपा के पास 40 सीटें थीं, उसकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के पास 31, निर्दलीय सात, और इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी के पास एक-एक सीट थी, वहां जेजेपी की स्थिति निर्णायक थी। इस कवायद में सबसे ज्यादा नुकसान जेजेपी को हुआ है। नई नवेली पार्टी ने खुद को इनेलो के असली उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया था और 10 सीटों के साथ भरपूर लाभ उठाया था। लेकिन अब खुद को सत्ता और निर्वाचन क्षेत्र दोनों के बिना महसूस कर रही है।

## उद्धव के बयान को गडकरी ने बताया अपरिपक्व और हास्यास्पद

**मुंबई।** केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के लिए आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव

ठाकरे के निमंत्रण को अपरिपक्व और हास्यास्पद बताया है। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से ताल्लुक रखने वाले गडकरी अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के नागपुर से मौजूदा सांसद हैं, जिन्होंने 2014 और 2019 दोनों आम चुनावों में सीट जीती है। 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली भाजपा की पहली सूची में गडकरी का नाम शामिल नहीं होने के बाद ठाकरे ने उन्हें यह प्रस्ताव दिया। सुझाव अपरिपक्व और हास्यास्पद है।

भाजपा में उम्मीदवारों को टिकट देने की एक प्रणाली है। 66 वर्षीय पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने यह विश्वास भी जताया कि पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 400 सीटें जीतेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगा।

लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है। महाराष्ट्र 543 सीटों वाली लोकसभा में 48 सदस्य भेजता है, जो उत्तर प्रदेश (80) के बाद सबसे अधिक है।

**प्रमुख समाचार**

### एक सामान्य कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री हैः यादव

**रायपुर।** मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र

ऐसा राजनीतिक दल है जहां मोहन यादव जैसा सामान्य कार्यकर्ता मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और यदि इससे भी बड़ा उदाहरण देखना है तो नरेंद्र मोदी से बड़ा उदाहरण और क्या होगा जहां एक चाय वाला विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होता है और ना सिर्फ प्रधानमंत्री बनता है अपितु प्रधानमंत्री के रूप में भारत के गौरव को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाने में अपना सर्वस्व लगा देता है। श्री यादव मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय के सभागार में रायपुर लोकसभा की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि हम सभी का समर्पण मां भारती के गौरव निर्माण के लिए है.

### एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी आयोग को भेजी

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड का डेटा सौंपा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया और उसे 12 मार्च को व्यावसायिक घंटों के अंत तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पोल पैनल को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बांड का विवरण प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए अपने फैसले में इसे असंवैधानिक करार दिया था। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि 12 अप्रैल 2019 के बाद से हुई चुनावी बॉन्ड की खरीद से जुड़े डीटेल्स 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमिशन को सौंप दे। ऐसे में लगभग इस पूरी अवधि के निकल जाने के बाद एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास 30 जून तक का वक्त देने का अनुरोध लेकर आया।

### शीना रानी ने भारत को दिया दिव्यास्त्र

**हैदराबाद।** भारत ने 11 मार्च (सोमवार) अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 की एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के साथ सफल टेस्टिंग की. अग्नि-5 मिसाइल मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है. यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है. वैसे अग्नि-5 मिसाइल की पहली टेस्टिंग अप्रैल 2012 में हुई थी, जबकि 11 मार्च को इसे एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट किया गया. इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है. यानी इसकी जद में चीन और पाकिस्तान आ जाएंगे. यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की रेंज में आएंगे. शायद इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्नि-5 मिसाइल को मिशन दिव्यास्त्र कहा. खास बात ये भी है कि इस दिव्यास्त्र को बनाने में महिला वैज्ञानिकों का हाथ है. डीआरडीओ की वैज्ञानिक शीना रानी ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था. आइए जानते हैं कौन हैं शीना रानी और उन्होंने कैसे इस प्रोजेक्ट पर काम किया. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की वैज्ञानिक शीना रानी 1999 से अग्नि मिसाइल सिस्टम पर काम कर रही हैं.

### मोदी सरकार पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं -शाह

**सिकंदराबाद।** सिकंदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे घोषणापत्र के पहले पन्ने पर क्या था? हम अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। 500 वर्षों से देश भर के श्रद्धालू चाहते थे कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर और रामलला को पूरे सम्मान के साथ विराजमान हों। कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही। वोट बैंक के लालच में आपने(कांग्रेस) राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। सिकंदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया है। आया राम, गया राम की राजनीति को खत्म करके देश में 10 साल की पूर्ण बहुमत सरकार चलाई है। इन 10 सालों में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। बीआरएस और कांग्रेस पर लाखों-करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर हमारे विरोधी भी 25 पैसे तक का आरोप नहीं लगा सके।

### लोस के साथ जम्मू-कश्मीर में विस चुनाव की भी सुगबुगाहट!

**नई दिल्ली।** लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन सभी के मन में बार बार एक ही सवाल है कि आखिर चुनावों की तारीखों का एलान कब होने जा रहा है। इस बीच खबर है कि आम चुनाव की घोषणा इस हफ्ते के अंत तक हो सकती हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव पूर्व मीटिंग का दौर भी 13 मार्च तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस बार भी आम चुनाव सात-आठ चरणों में हो सकते हैं। आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अलग-अलग राज्यों का दौरा कर चुका है। आयोग 11 मार्च से 13 मार्च तक जम्मू-कश्मीर के दौरे पर है। इस दौरान चुनाव आयोग ये भी आकलन कर रहा है कि राज्य में चुनाव कब हो सकते हैं। इस दौरे के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान होने की संभावना है। 2019 के आम चुनाव की तारीख 10 मार्च को घोषित की गई। सात चरणों में चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हुई थे। जबकि मतों की गिनती 23 मई को हुई थी। अधिकारियों के अनुसार, बोर्ड परीक्षा, त्योहार और सुरक्षाकर्मियों की उपलब्धता को देखते हुए चुनाव की तारीखें तय की जा रही हैं।

# दांव पर क्षेत्रीय नेताओं का भविष्य

**प्रभु चावला**

लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं के उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी करना उनका शगल है। कांग्रेस के लिए मृत्युलेख लिखना सामान्य खेल है। नरेंद्र मोदी ने पहले ही अपनी पार्टी की जीत की घोषणा कर दी है। खोखले दक्षिणपंथी विशेषज्ञ कांग्रेस को 50 से कम सीटें दे रहे हैं। जुझारू राष्ट्रीय पार्टी की अनुपस्थिति में अब विपक्ष के क्षेत्रीय क्षत्रपों को अपने यहां मोदी का रथ रोकना है या विलुप्त हो जाना है। लोकसभा का चुनाव केवल मोदी की तीसरी पारी के बारे में नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन, सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी की क्षेत्रीय विचारधाराओं के राजनीतिक स्थायित्व के बारे में भी है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव यह सिद्ध करना होगा कि वे अपने प्रख्यात पिताओं के योग्य उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने अपने राज्यों पर मजबूत पकड़ बनाकर रखी थी और प्रधानमंत्रियों को बनाने एवं नहीं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। उत्तर भारत में कांग्रेस सीधी लड़ाई में भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा का बहुमत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और दिल्ली के नतीजों पर निर्भर करेगा। इन राज्यों में 348 सीटें है, जिनमें भाजपा के पास 169 तथा इंडिया गठबंधन के पास 126 सीटें हैं। शेष भारत राष्ट्र समिति जैसी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों, वामपंथी पार्टियों और अन्यों के पास हैं।

उत्तर प्रदेश 50 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भविष्य तय करेगा, जिनके पिता की बड़ी हैसियत के कारण एक बार समाजवादी पार्टी ने 36 लोकसभा सीटें और विधानसभा में लगभग 60 प्रतिशत सीटें जीती थी। साल 2012 में अखिलेश ने राज्य में विजय पायी थी, पर उसके बाद वे लगातार हारते रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने मायावती से गठबंधन किया था, पर पांच सीट ही जीत सके थे। इस बार वे राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं। मोदी और योगी सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं।

बिहार में 34 साल के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या तो अस्त हो जायेंगे या अपने पिता लालू यादव के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी हासिल करेंगे। अभी लोकसभा में राजद का एक भी सदस्य नहीं है और उसकी सहयोगी कांग्रेस 2019 में केवल एक सीट जीत पायी थी। शेष 39 सीटें भाजपा-नीतीश कुमार की झोली में गयी थी। बिहार में तेजस्वी के पास अपनी जगह बनाने और राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का मौका है। मोदी की संख्या पर असर से उनकी ताकत का आकलन होगा।

महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भावी प्रासंगिकता का निर्णय होगा। ये दोनों राष्ट्रीय पहुंच वाले सत्ता के स्थानीय खिलाड़ी हैं। वे दशकों से राज्य की राजनीति पर हावी हैं, पर हाल में दल-बदल में दोनों ने अपने दल खो दिये हैं। यह चुनाव तय करेगा कि वे अपने काडर और सांगठनिक समर्थन को बरकरार रख सकते हैं या नहीं। साल 2019 में पवार, जिनके पास अब नया चुनाव चिह्न है, भाजपा-शिव सेना गठबंधन के विरुद्ध केवल चार सीटें जीत सके थे।

पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी और मोदी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पिछली बार लोकसभा में 18 और फिर विधानसभा में 77 सीटें जीतकर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। मोदी ने 370 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीते दो साल से पश्चिम बंगाल युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। दमदार ममता ने भाजपा को राज्य से बाहर करने की प्रतिज्ञा ली है।

तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के तेजी से गायब होते जाने के साथ 71 साल के एमके स्टालिन और द्रविड़ पहचान को भाजपा की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की 39 सीटों में 23 द्रमुक और आठ कांग्रेस के पास हैं। भाजपा ने 15 सीटों का लक्ष्य तय किया है। भाजपा जाति समीकरण को तोड़ने और सनातन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ऐसे में स्टालिन को जीत के लिए नये द्रविड़ अस्त्र की आवश्यकता होगी। केरल में दो सेकुलर गठबंधनों- सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा और कांग्रेस की अगुवाई में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट- के प्रतिरोध के कारण भाजपा कभी एक सीट भी नहीं जीत पायी है। पहली बार इन गठबंधनों को भाजपा से अच्छी चुनौती मिल रही है।

कर्नाटक, झारखंड, पंजाब और दिल्ली में भगवा सुनामी रोकने के लिए निगाहें स्थानीय नेतृत्व की क्षमता पर लगी हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को आशा है कि भाजपा की सीटें 25 से घटकर 15 से कम रह जायेंगी और कांग्रेस शून्य से 10 के आंकड़े पर आ जायेगी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दिल्ली एवं पंजाब में भाजपा को शून्य पर लाने के लिए कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर रहे हैं। कांग्रेस अगली लोकसभा के गणित और नये भारत की राजनीति को अकेले निर्धारित नहीं कर सकती। परिणाम क्षेत्रीय नेताओं और जातिगत राजनीति के उभार या खात्मा तय करेंगे। विडंबना है कि आगामी दशकों की राजनीति की दिशा मोदी की जीत नहीं, बल्कि उनके विरोधियों की हार तय करेगी।

# हाईकोर्ट ने ओपन जेल खोलने सरकार को विचार करने की दी सलाह

■ छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जेल, जिला जेल और उप जेल के आंकड़ों के आधार पर हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों की परेशानी और बढ़ती संख्या को लेकर स्वत- संज्ञान लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की जेलों में 20 साल से ज्यादा कारावास की सजा वाले कैदी के अलावा क्षमता से ज्यादा कैदियों की संख्या होने से व्यवस्था खराब होने की बात सामने आई है।

एक मामले के आरोपी के परिजन ने विभिन्न तारीखों पर हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि मोहम्मद अंसारी की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत 2010 से जेल में बंद है। हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल 2023 को उनकी याचिका खारिज भी कर दी है। पत्र में कहा गया है कि घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति के जेल में बंद होने के कारण वे लोग बदहाली में जीवन जी रहे हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में चल रही है। इस मामले में मिले पत्र के आधार पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

## पत्र मिलने पर कोर्ट हुआ गंभीर

पत्र में बताया गया है कि जेलों की क्या

व्यवस्था है। पत्र के माध्यम से कोर्ट को 6 बिंदुओं पर एकत्र किए गए डाटा की जानकारी लगी, जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित केंद्रीय जेल और जिला जेल में महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चे, 20 वर्ष से अधिक की सजा वाले कैदी, जेल की क्षमता और वास्तव में जेल में रखे गए कैदियों की कुल संख्या, बढ़ाई, प्लंबर, पेंटर, माली, किसान जैसे कुशल पेशेवर कैदियों की कुल संख्या, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आने वाले कैदी और जेल से भागने वाले कैदियों की संख्या कितनी है। इसमें जानकारी जुटाई गई है, जिसमें पाया गया की जेल में महिला कैदियों के साथ 82 बच्चे रह रहे हैं। 340 अपराधी ऐसे हैं, जिन्हें 20 वर्ष से अधिक कारावास की सजा हुई है।

हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई के दौरान कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में ओपन जेल की व्यवस्था करने और अन्य सुधार करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए जाते हैं। सरकार इस पर विचार करें। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

कोर्ट ने कहा है कि सुधारात्मक सजा के साथ सलाखों वाली पारंपरिक अमानवीय जेल सही नहीं है, बल्कि अधिक उदार और खुली जेल की अवधारणा का समर्थन होना चाहिए, जो न्यूनतम सुरक्षा के साथ एक विश्वास आधारित जेल है। यह भी कहा गया है कि भारत में खुली जेल की अवधारणा नई नहीं है। देश में पहले से ही तीन राज्यों में खुली जेल की संख्या सबसे अधिक है। एक खुली जेल अनुकूल माहौल प्रदान करती है। ऐसी जेल अपराधी को जेल से रिहा होने से पहले भी सामाजिक मेल-जोल में मदद करेगी। ऐसे कैदियों की काफी संख्या है जो कुशल पेशेवर हैं, जिनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

## ओपन जेल क्या है?

भारत के तीन राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में खुली जेल की व्यवस्था है। खुली जेल का मतलब यह है कि अच्छे आचरण और चाल चलन के साथ ही भरोसेमंद कैदियों को जिनके पास हुनर है, उन्हें उनके काम पर जाने दिया जाता है। वह सुबह जेल से काम के लिए निकलते हैं और इसके बाद शाम होते ही वह वापस जेल पहुंच जाते हैं। इस व्यवस्था को खुली जेल या ओपन जेल व्यवस्था कहा जाता है। कैदियों को दिन के समय उनके काम पर जाने दिया जाता है और रात होते ही वे लौट आते हैं। यह सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों का अभिन्न अंग माना जाता है, जिसके तहत किसी अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाता है और वह अपने रिहा होने के बाद वापस समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर अपना जीवन चला सके और अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके।

# धमतरी में अनोखा प्रदर्शन होली से पहले ही नगाड़ा नगाड़ा

**धमतरी।** धमतरी नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक नहीं होने का मुद्दा अब गरमा गया है। पहले बीजेपी पार्षदों और नेताओं ने धमतरी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अब बीजेपी पार्षदों ने निगम दफ्तर के सामने ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया है।

भाजपा पार्षदों का कहना है कि साढ़े चार साल में केवल चार सामान्य सभा की बैठक हो पाई है, जिसमें से एक बैठक में महापौर विजय देवांगन सभा अधूरी छोड़कर चले गए थे। भाजपाई पार्षदों ने चुनाव आयोग के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन दिया है। इसमें विशेष बजट बैठक बुलाने की परमिशन देने की मांग रखी गई है। बीजेपी पार्षदों ने निगम सभापति अनुराग मसीह पर भी गंभीर आरोप लगाएं हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है।

धमतरी महापौर विजय देवांगन ने भाजपा पार्षदों पर तंज कसा है। विजय देवांगन ने कहा, भाजपा के चुनाव आयोग से मांगी गई अनुमति का समर्थन करता हूं। भाजपाई महापौर की दावेदारी करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन करके यह जताना चाह रहे हैं कि कौन सक्षम नेता है।

दरअसल, धमतरी के कांग्रेसी महापौर हमेशा से भाजपा पार्षदों के निशाने पर रहे हैं। लगातार कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पार्षद धमतरी मेयर का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा की अगुवाई में निगम के बाहर प्रदर्शन कर धमतरी मेयर विजय देवांगन और सभापति अनुराग मसीह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। अब बजट बैठक न करने को लेकर प्रदर्शन किया गया है।

# सीआईएसएफ का 55वां स्थापना दिवस भिलाई में आयोजित

## महिला कमांडो ने दी मार्शल आर्ट की प्रस्तुति

**भिलाई।** केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने मंगलवार को अपना 55वां स्थापना दिवस भिलाई में मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुऐ। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। साथ ही भारत के प्रमुख कारखानों सहित एयरपोर्ट और मेट्रो को सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं।

भिलाई के उतई स्थित सीआईएसएफ के केंद्रीय ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ कई आतंकियों ने हमला कर दिया था, लेकिन सीआईएसएफ की विशेष टुकड़ी में तैनात कमांडो ने आतंकियों को नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। हमला करने वाले आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। दरअसल यह मात्र एक डेमोस्ट्रेशन था, जो कि सीआईएसएफ के 55 वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। सबसे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान सीआईएसएफ के अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किया गया। सीआईएसएफ की महिला कमांडो के द्वारा प्राचीन मार्शल आर्ट की प्रस्तुति दी गई। देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों की रक्षा, और परमाणु ऊर्जा संस्थानों में सीआईएसएफ किस तरह से अपनी भूमिका निभाता आ रहा है।

साथ ही सीआईएसएफ का अग्निशमन विभाग भीषण आगजनी में किस तरह से कार्य करता है। इसका भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सीआईएसएफ में 20 हजार का स्ट्रेंथ बढ़ा है, जिसमें एक बटालियन महिलाओं की भी है। आज सीआईएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी।

# एलएलबी सेमेस्टर 2 रिजल्ट से धमतरी के स्टूडेंट्स नाखुश

## पुनर्मूल्यांकन की मांग

**धमतरी।** धमतरी पीजी कॉलेज के एलएलबी छात्र बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। स्टूडेंट का कहना है कि हाल ही में रविवि ने सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट जारी किया है, जिससे वे परीक्षा परिणामों से नाखुश हैं। स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धमतरी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि पुनर्मूल्यांकन कर छात्र हित में फैसला लिया जाए।

एलएलबी पार्ट-2-सेमेस्टर प्रथम (विधि विभाग) बाबु छोटेलाल श्रीवास्तव पीजी कॉलेज धमतरी केस्टूडेंट्स ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने एलएलबी पार्ट-2-सेमेस्टर प्रथम का रिजल्ट घोषित किया है। जिसमे रविवि के परीक्षा विभाग द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन किये जाने के कारण छात्र-छात्राओं का परिणाम बहुत खराब आया है। इस वजह से एलएलबी पार्ट-2-सेमेस्टर प्रथम का परिणाम 44.04 प्रतिशत यानी कि 50 प्रतिशत से भी कम है।

एलएलबी स्टूडेंट ने कहा हाल ही में हुए सेमेस्टर एग्जाम में परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं है, जिससे सभी छात्र नाखुश हैं। 50 फीसदी से भी कम सभी के रिजल्ट आए हैं, जो संदेह पैदा कर रहा है। हमारी मांग है कि छात्र हित में सभी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की सत्यता से पुनर्मूल्यांकन किया जाए, ताकि उनके इस परिणाम की वजह से हमारे भविष्य तथा चौथे सेमेस्टर के परीक्षा प्रवेश में कोई बाधा न हो।

इस संबंध में धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा पूरा विषय यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। विद्यार्थियों के आवेदन यूनिवर्सिटी को प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही छात्र आरटीआई आवेदन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

एलएलबी पार्ट-2-सेमेस्टर प्रथम (विधि विभाग) बाबु छोटेलाल श्रीवास्तव पीजी कॉलेज धमतरी के सभी विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। साथ ही उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं की सत्यता से पुनर्मूल्यांकन करने की मांग रखी है।

# बलरामपुर में सत्याग्रह आंदोलन रैली, कर्मचारी सड़क पर उतरे

## चार महीनों से नहीं मिला वेतन

**बलरामपुर।** छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ ने जिला मुख्यालय बलरामपुर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर चांदो चौक से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक सैकड़ों कर्मचारियों ने सत्याग्रह आंदोलन निकाला। इन कर्मचारियों ने कहना है कि उन्हें करीब चार महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

बलरामपुर जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ट्राइबल विभाग विभिन्न शासकीय विभागों और छात्रावास में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बीते चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। बीते सात महीनों से उन्हें श्रम सम्मान की राशि भी नहीं मिली है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए अपना घर चलाना और परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है।

संभागीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा हमारी सिर्फ दो मांगें है पहली तो सात महीनों से लंबित श्रम सम्मान की राशि है, उसे हमें तत्काल प्रदान किया जाए। चार महीनों से लंबित हमारे मूल वेतन को भी तुरंत दिया किया जाए। जब मंत्रालय से सात बार लेटर डिस्पैच हो रहा है, कमिश्नर कार्यालय से दो बार लेटर डिस्पैच हो रहा है, तो जिला प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सात महीनों से हमारे श्रम सम्मान की राशि लंबित क्यों है। पूरे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आज रोड पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो वे मुख्यमंत्री निवास जाएंगे। मुख्यमंत्री के रायपुर या फिर जशपुर के बगिया मुख्यमंत्री निवास पर जाने की बात प्रदर्शनकारी कर रहे हैं।

## छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

### ताम्रध्वज साहू ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई चुनावी रणनीति

**महासमुंद।** कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और दुर्ग लोकसभा के पूर्व सांसद रहे ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज पहली बार ताम्रध्वज साहू महासमुंद पहुंचे, जहां उनका जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। महासमुंद सीट से लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए विश्वास जताने को लेकर उन्होने शीर्ष नेताओं का आभार जताया और उनके भरोसे को कायम रखने की बात कही। इसके बाद ताम्रध्वज साहू ने कार्यकर्ताओं से साथ बाठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मीडिया से चर्चा करते हुए ताम्रध्वज ने कहा, अगर मैं लोकसभा जीतकर निर्वाचित हुआ तो अपने कार्यकाल में मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा, जिससे महासमुंद की जनता को सर झुकाना पड़े। इस बात का विश्वास मैं दिलाता हूं।

### कोण्डागांव में जंगल जतरा 2024 का आयोजन

**कोंडागांव।** आज कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम ग्राउंड में जंगल-जतरा 2024 का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर करीब एक लाख वनवासी जंगल-जतरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बस्तर संभाग की 216 प्राथमिक वनोपज समितियों और 2 हजार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से जुड़े हुए लोग हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वन विभाग की योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि तथा सामग्री वितरित की जायेगी। जंगल जतरा कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के 9 गांव का खसरा वितरित किया जायेगा। साथ ही वन समितियों को लाभांश राशि और बीमा राशि का वितरण भी किया जाएगा। बस्तर संभाग में 52 वन-धन विकास केन्द्र एवं 317 हाट बाजार केन्द्र संचालित है, जिससे 1180 संग्रहण ग्राम जुड़े हुए है।

### नारायणपुर के सरकारी स्कूल नहीं सुरक्षित, 3 टीचर्स पर केस

**नारायणपुर।** छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने टीचर पर बड़ा आरोप लगाया। स्कूल की नाबालिग छात्राओं ने तीन शिक्षकों पर कथित तौर पर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। मामला नारायणपुर के एडका रोड का है। महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल कल्याण समिति को नारायणपुर के सरकारी मिडिल स्कूल में छात्राओं के यौन शोषण की शिकायत मिली थी। आरोपी स्कूल के ही तीन टीचर्स पर लगाए गए। मामले को गंभीर मानते हुए बाल विकास विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) ने स्कूल का दौरा किया। छात्रों के बयान दर्ज कराए गए। स्कूल की पांच से छह नाबालिग छात्राओं ने स्कूल के तीन टीचर्स पर क्लास में उनके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। टीम ने स्कूल के दूसरे शिक्षकों और प्रिंसीपल का भी बयान दर्ज कराया। जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की गई। छात्राओं के बयान और डीसीपीयू की रिपोर्ट के आधार पर विभाग की टीम ने पुलिस को आरोपी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया।

### सीआरपीएफ जवान के मकान को चोरों ने बनाया निशाना

**कांकेर।** सीआरपीएफ में आरक्षक के पद पर पदस्थ जवान छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आतुरगांव आया था। छुट्टी के दौरान महाशिवरात्रि का मेला देखने के लिए अपने गृह ग्राम कापसी गया। उसी दौरान अज्ञात चोर ने आतुरगांव के घर को सूना पाकर जवान के घर धावा बोलते हुए घर में रखे नगद व जेवरात समेत कुल एक लाख 25 हजार की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सड़कपारा आतुरगांव निवासी जवान आधार सिंह (40) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह सीआरपीएफ में आरक्षक के पद पर 211 बटालियन मेचका सोदुर जिला धमतरी में पदस्थ हैं। 17 फरवरी को छुट्टी लेकर अपने घर आतुरगांव आया था। सात मार्च को शाम करीब चार बजे अपने घर में ताला बंदकर पत्नी अंजु कावड़े और छोटी बच्ची मानवी को लेकर अपने गृह ग्राम कापसी महाशिवरात्रि मेला देखने गया था। वहां से 12 मार्च को सुबह करीब नौ बजे परिवार के साथ सुबह करीब नौ बजे आतुरगांव वापस आया तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है।

### रिवॉल्वर की नोक पर लूटे रुपये और शराब

**कोरबा।** नकाबपोश तीन लुटेरों ने गोपालपुर स्थित शराब दुकान में धावा बोल दिया। लुटेरों ने डेढ़ लाख रुपये और कुछ महंगी शराब लूट ली। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि किस तरह लुटेरे रिवॉल्वर की नोक पर शराब दुकान के भीतर घुसते हैं और पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। युवकों ने बंद शराब दुकान से शराब लेने के बहाने पहले चौकीदार को झांसे में लिया, फिर इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। शराब दुकान पर तैनात अजय केवंट ने बताया कि रात में 10 बजे दुकान बंद हो गई थी। इसके बाद एक नकाबपोश युवक दुकान के पीछे की तरफ से आया और शराब मांगने लगा। उसके दरवाजा खुलवाकर बात करने की कोशिश की, तभी पीछे से दो युवक और आ गए। उन्होंने कनपटी पर रिवॉल्वर लगा दिया। इसके बाद तीनों ने अंदर घुसकर रुपये और शराब उठा ले गए। दर्री थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

# बस्तर लोकसभा सीट की जंग में कौन जीतेगा बाजी

**जगदलपुर।** छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। इनमें बस्तर लोकसभा सीट अपने आप में काफी अहम माना जाता है। बस्तर सीट इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में आदिवासियों की बहुलता है। बस्तर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाका है। हालांकि यहां धीरे-धीरे हालात में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में सालों बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार कांग्रेस के लिए बस्तर की सीट पर जीत हासिल करना बड़ी चुनौती होगी क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने महेश कश्यप पर भरोसा जताया है। हालांकि अब तक कांग्रेस ने इस सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है।

साल 1951 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1996 तक यह कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। हालांकि साल 1996 में पहली बार यहां की जनता ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुना। यह सीट 1998 से बीजेपी के पास है। पिछले दो दशक से लगातार कश्यप परिवार के लोग यहां से जीतते आ रहे हैं। यहां की कुल आबादी करीब 22 लाख है। यह आदिवासी बहुल है और यहां की करीब 65 फीसदी आबादी आदिवासियों की है। आठ विधानसभा सीटें इस सीट के अंतर्गत पड़ती है। इनमें बीजापुर और कोंटा विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है।

अगर समस्याओं की बात करें तो इस क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं यहां आम है। इसके अलावा कई क्षेत्र पहुंचविहीन है। लोगों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में नक्सलियों का

दबदबा है। हालांकि अब पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी बस्तर लोकसभा क्षेत्र का कई हिस्सा नक्सलियों का दंश झेल रहा है। यहां रहने वाले ग्रामीणों का जीवन जंगल पर ही आधारित है। इन लोगों के जीवन से विकास कोसों दूर है। शिक्षा तो दूर की बात है, इन्हें बिजली, सड़क और पेयजल के लिए भी काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। हालांकि ये लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देते हैं।

साल 1999 के लोकसभा चुनाव में बस्तर संसदीय क्षेत्र में कुल 954405 मतदाता थे। कुल वोटों की संख्या 356603 थी। इस सीट से बीजेपी नेता बलिराम कश्यप ने जीत दर्ज की। बलिराम कश्यप को कुल 155421 वोट मिले थे। वहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र कर्मा को 134684 वोट मिले थे। वहीं, साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बस्तर संसदीय क्षेत्र में कुल 1039442 मतदाता थे। इस सीट से एक बार फिर बीजेपी नेता बलिराम कश्यप ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 212893 वोट मिले थे। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र कर्मा को हार का सामना करना पड़ा। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बस्तर संसदीय क्षेत्र में कुल 1193116 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया था। इस सीट पर इस बार भी बीजेपी उम्मीदवार बलिराम कश्यप को 249373 वोटों से जीत हासिल हुई। वहीं, कांग्रेस के शंकर सोढी को हार का सामना करना पड़ा।

साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बस्तर क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1298083 थी। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश कश्यप को 385829 वोटों से जीत मिली। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार दीपक कर्मा हार गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बस्तर में वोटरों की संख्या 1379122 थी। हालांकि इस सीट पर इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार दीपक बैज ने 402527 वोटों से जीत हासिल की। जबकि बीजेपी उम्मीदवार बैदु राम कश्यप को हार का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कुल 41667 नोटा वोट पड़े थे।

## बस्तर सीट का चुनावी इतिहास

साल 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार मुचाकी कोसा ने इस सीट पर जीत हासिल की। साल 1957 में कांग्रेस उम्मीदवार सुरति किस्तैया ने जीत दर्ज की। साल 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार लखमु भवानी जीते। साल 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार जे सुंदरलाल को मिली जीत। साल 1971 में निर्दलीय उम्मीदवार लंबोदर बलियार ने जीत हासिल की। साल 1977 में बीएलडी उम्मीदवार द्रिगपाल शाह केशरी शाह ने जीत हासिल की थी। साल 1980 में कांग्रेस से लक्ष्मण कर्मा ने जीत हासिल की। साल 1984 में कांग्रेस से मनकुरम सोढ़ी ने जीत दर्ज की। साल 1989 में कांग्रेस से मनकुरम सोढ़ी ने जीत हासिल की। साल 1991 में कांग्रेस के मनकुरम सोढ़ी जीते। साल 1996 में कांग्रेस के महेन्द्र कर्मा ने जीत हासिल की। साल 1998 में बीजेपी के बलिराम कश्यप ने जीत हासिल की। साल 1999 में बीजेपी से बलिराम कश्यप को जीत मिली। साल 2004 में भी बीजेपी से बलिराम कश्यप को जीत मिली। साल 2009 में बीजेपी के बलिराम कश्यप को जीत मिली। साल 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप को जीत मिली। साल 2019 में कांग्रेस से दीपक बैज को जीत मिली।

# प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को दी 85 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात

## नरेंद्र मोदी ने कहा- देश और छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने तेज होगा रेलवे का आधुनिकीकरण, रेलवे के कई प्रोजेक्ट लॉन्च

**रायपुर।** पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को छत्तीसगढ़ को वर्चुअली 85 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने गुजरात के अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बटन दबाकर छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ी 85 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन में 34 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (एक स्टेशन एक उत्पाद) स्टॉल लॉन्च की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद कमांड सेंटर से हरी झंडी दिखाकर 10 नई वंदे भारत रेल गाड़ियों को भी रवाना किया।

रेलवे स्टेशन में आयोजित लोकार्पण समारोह में प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम विष्णु देव साय, रायपुर सांसद सुनील सोनी, मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, राजेश मूणत और जिला और रेल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 670 से अधिक रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों से भी लोग वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

पीएम ने कहा कि रेलवे के इतिहास में पिछले 100 वर्षों में भी एक कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में रेल परियोजनाओं के शुभारंभ का कार्यक्रम आज पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस नये साल के पिछले 75 दिनों में ही देश में 11 लाख करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में देश का एक बड़ा कदम बताया। भारतीय रेलवे लंबे समय से राजनीति और क्षेत्रवाद का शिकार रही है। रेलों में डब्बे बढ़ाना, स्टॉपेज बढ़ाना ही रेल की प्रगति के मायने रहें थे। बीते समय में रिजर्वेशन की लंबी लाईनें, दलाली और कमिशन के साथ गंदगी ने भारतीय रेल की स्थिति नरकीय बना दी थी। वर्ष 2014 में देश के 9 राज्यों की राजधानियां रेल नेटवर्क से अछूती थी। 10 हजार से अधिक रेल क्रॉसिंग फाटक विहीन थी।

### बीजेपी सरकार ने रेल को नरक जैसी स्थिति से बाहर लाने की इच्छाशक्ति दिखाई

पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने भारतीय रेल को नरक जैसी स्थिति से बाहर लाने की इच्छा शक्ति दिखाई है। रेवले के बजट को समान्य बजट के साथ शामिल कर छह गुना बढ़ाया गया है। इससे दूसरे मदों से मिले राजस्व का हिस्सा भी रेलवे के विकास के लिए उपयोग किया जा सका है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में भारतीय रेलवे का ऐसा कायाकल्प होगा कि किसी ने भी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बुजुर्गों और हमनें जो भुगता है वो आने वाली पीढ़ी नहीं सहेगी, यह मोदी की गारंटी है। देश को समृद्ध और औद्योगिक रूप से विकसित करने में रेल की बहुत बड़ी भूमिका है। सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों के लिए अलग-अलग रेल लाईनें स्थापित कर दोनों की स्पीड बढ़ाई गई है। फ्रंट कॉरीडोर बनाकर तेजी से डबल डेकर माल गाड़ियों से माल ढुलाई शुरू हो गई है। आधुनिक रेल इंजन, सुसज्जित कोच फैक्ट्रियां, गति शक्ति कार्बो टर्मिनल जैसी अधोसंरचनाएं भारत को विकसित बनाने की दिशा में तेजी से सकारात्मक योगदान दे रहीं है।

### पीएम ने इन परियोजनाओं का किया लोकार्पण

बिलासपुर में एक रेल कोच रेस्टोरेंट। बिलासपुर में वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो। दुर्ग कोचिंग डिपो पीट लाइन का अपग्रेडेशन। भिलाई मेमू शेड का विस्तार। जांजगीर, नैला, पेंड्रा रोड में जनौषधि केंद्र का लोकार्पण। अंबिकापुर में पिट लाइन का शिलान्यास।

### कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए

उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना आधुनिक तकनीक पर लोकोमोटिव इंजन निर्माण से लेकर नई पटरियां बिछाने, स्टेशनों के आधुनिकीकरण जैसे अनेकों काम देश में हुए है। हमारे देश में बने लोकोमोटिव श्रीलंका सुडान, मोजाबिंक जैसे देशों को निर्यात किए जा रहें है। हम सौर उर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहें है। स्टेशनों पर जल औषधी केन्द्र खोल रहें है, स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और स्व-सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए स्थानीय शिल्प और कलाकृतियों को स्टेशनों पर बिक्री के लिए स्टॉल खोले जा रहें है। जिसका लाभ सीधे गरीब कारीगरों को मिल रहा हैं। रेलवे में आधुनिक तकनिकों के उपयोग से देश के कोने-कोने को रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तो हो ही रहा है इसके साथ ही नये निवेश की गारंटी भी मिल रही है और रोजगार के अवसर भी खुल रहें है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे विकास के काम राजनीतिक रूप से सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश बनाने के लिए है।

### राज्यपाल विश्वभूषण बोले- रेलवे भारत की लाइफ लाइन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्य अतिथि की आसंदी से कहा कि रेलवे भारत की लाइफ लाइन है। रेल के विकास का सीधा प्रभाव देश के विकास और आर्थिक उन्नति पर पड़ता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे का उल्लेखनीय विकास और आधुनिकीकरण हो रहा है। कई रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है।प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेलवे विकास के राजमार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। वन्दे भारत ट्रेनों का चलना और अमृत स्टेशनों का निर्माण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि रेलवे देश की जीवन रेखा है। रेलवे के विकास का सीधा प्रभाव देश के विकास पर होता है। भारतीय रेलवे अपनी अधोसंरचना में तेजी से सुधार करते हुए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है। प्रमुख स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों के लिए स्टॉल, रेल कोच रेस्टोरेंट तथा जन औषधि केन्द्र खोलकर कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिल रहें है। इन केन्द्रों से वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय स्वदेशी उत्पादों का बाजार उपलब्ध कराने और कुम्हारों, बुनकरों जैसे स्थानीय शिल्पकारों को अजीविका के अवसर देने के साधन भी यह केन्द्र बन रहें है। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ को लगभग डेढ़ सौ करोड़ रूपये की रेल परियोजनाओं की सौगात देने पर प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

### विश्वस्तरीय लेवल पर डेवलप हो रहे छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशन

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल सेवाओं का रिकॉर्ड स्तर पर आधुनिकीकरण और विकास हो रहा है। यात्री सुविधाओं और सेवाओं के मामले में भारतीय रेल वैश्विक स्तर की श्रेष्ठ सेवाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री आज पूरे देश में 85 हजार करोड रुपए की लागत की 6 हजार परियोजना का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को उदारतापूर्वक काफी कुछ दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेलवे से संबंधित 36 हजार 968 करोड रुपए की लागत की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6896 करोड़ का आवंटन मिला है। छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत बिक्री केन्द्रों का शुभारंभ करने और जांजगीर-नैला तथा पेंड्रा रोड स्टेशन पर जन औषधि केन्द्र खोलने के साथ अन्य दूसरे विकास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने आशा की कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विकास की नए सोपान गढ़े जाएंगे जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बेहतर अवसर मिलेंगे।

## संक्षिप्त समाचार

### छत्तीसगढ़ के 68.53 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हुआ 636.44 करोड़ रु.

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपये ट्रांसफर किया जा चुका है। खातों में पैसा देखकर महिलाओं की मन गदगद हो गया है। काफी उत्साह नजर आ रही हैं। इस योजना के तहत प्रदेश की 68.53 लाख महिलाओं के खातों में 636.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार योजना की शेष महिला हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 मार्च को छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को एक-एक हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया गया। योजना के तहत एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रुपये महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित किए जाएंगे।

### रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा को राज्य शासन ने सौंपी दो बड़ी जिम्मेदारी

**रायपुर।** रायपुर रेंज के आईजी आईपीएस

अमरेश मिश्रा को छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण और एंटी करप्शन ब्यूरो (ईओडब्ल्यू, एसीबी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य शासन ने दो और बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए आदेश जारी किया है। आईपीएस अमरेश मिश्रा 2005 बैच के अधिकारी हैं। इसके लिए राज्य शासन ने देर रात आदेश जारी किया है।

### निगम ने गंदगी फैलाने, डस्टबिन नहीं रखने वाले दुकानदारों पर लगाया जुर्माना

**रायपुर।** नगर निगम रायपुर के द्वारा आज

बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया गया, इस दौरान कचरा एवं गंदगी फैलाने एवं दुकानों में डस्टबिन नहीं रखने वाले दुकानदारों को समझाईश देकर उनसे जुर्माना वसूला गया। जोन 1 स्वास्थ्य विभाग ने गोंदवारा ब्रिज के पास अभियान चलाया एवं 8 दुकानदारों पर कचरा गंदगी फैलाने पर 800 रूपये जुर्माना कर उन्हें समझाईश दी गयी। जोन 2 की टीम ने 11 दुकानों में गंदगी फैलाने एवं डस्टबिन नहीं मिलने पर 3800 रूपये का जुर्माना सम्बंधित दुकानदारों से भविष्य के लिए कड़ी समझाईश देकर वसूला। जोन 4 की टीम ने बाजार क्षेत्र में 5 दुकानदारों से गंदगी फैलाने एवं डस्टबिन नहीं रखे जाने पर 1200 रूपये जुर्माना वसूला। जोन 5 की टीम ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह वार्ड के बाजार क्षेत्र में 5 दुकानों में गंदगी कचरा फैलाने, डस्टबिन नहीं रखने पर कुल 1600 रूपये का जुर्माना वसूला। जोन 8 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाजार में 5 दुकानों में डस्टबिन नहीं मिलने एवं 5 दुकानों पर गंदगी फैलाने पर कुल 1000 रूपये का जुर्माना कड़ी चेतावनी भविष्य के लिए देते हुए वसूला। जोन 9 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दुबे कॉलोनी मोवा, गीतांजलि कॉलोनी शंकर नगर में औचक निरीक्षण कर 6 दुकानों में कचरा, गंदगी मिलने पर कुल 1400 रूपये, 7 दुकानों में डस्टबिन नहीं मिलने पर कुल 700 रूपये का जुर्माना वसूला। जोन 10 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाजार क्षेत्र में 10 दुकानों में गंदगी फैलाये जाने, डस्टबिन नहीं रखे जाने पर 1100 रूपये का जुर्माना वसूला।

# बिलासपुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू

■ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की शुरुआत

**रायपुर/बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय रायपुर में वीडियो कांफ्रेंस से हरी झंडी दिखाकर बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट चकरभाठा से बिलासपुर-दिल्ली और बिलासपुर-कोलकाता सीधी फ्लाइट सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने नई हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई दी। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासा देवी केंवट विमानतल पर मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकें। आज बिलासपुरवासियों की लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी मांग पूरी हो गई। बिलासपुर से

कोलकाता और बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। मेरी ओर से इसके लिए बिलासपुरवासियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिलासपुर हवाई अड्डे को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। जल्द ही यहां नाइट लैंडिंग की सुविधा भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है। इस हवाई सेवा का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। आज जगदलपुर के लिए भी खुशखबरी है। आज जगदलपुर से जबलपुर के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो रही है। इस हवाई सेवा का लाभ बस्तर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। यहां व्यापार और पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

### बस्तर से दिल्ली के लिए फ्लाइट हुई रवाना, वॉटर कैनन से किया स्वागत

**जगदलपुर।** बस्तर की बहुप्रतीक्षित मांग आखिरकार मंगलवार को पूरी हो गई, जब दिल्ली से जगदलपुर हवाई सेवा से जुड़ गया। एलायंस एयर की फ्लाइट दिल्ली से शुरू होकर जबलपुर होते जगदलपुर सुबह 11.30 बजे लैंड किया। विमान के आगमन पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर उसका वाटर कैनन से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक किरण देव ने प्रधानमंत्री, विमानन मंत्रालय, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए दिल्ली के लिए सीधी सेवा के लिए बस्तर वासियों को बधाई दी। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को फ्लाइट यहां से ऑपरेट होगी। दिल्ली से सुबह 7.30 बजे उड़ान भरेगी, 9.50 को जबलपुर पहुंचेगी और वहां 30 मिनट का स्टॉपेज लेकर 10.15 बजे जगदलपुर के लिए उड़ान भरकर 11.35 बजे जगदलपुर पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे फ्लाइट यहां से रवाना होगी। दोपहर 1.25 बजे जबलपुर पहुंचेगी। वहां से फ्लाइट 1.50 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी, जो कि दोपहर 3.55 बजे दिल्ली पहुंचेगी। पहले दिन शहर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने 27 यात्रियों ने टिकट बुक करवाई है। इसी विमान से 24 यात्री जगदलपुर पहुंचे। विमान की दिल्ली के लिए सेवा प्रारंभ होने पर कलेक्टर विजय दयाराम के ने विमान सेवा के विस्तार के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ ही बस्तर में विमान सेवा बढ़ाने का लगातार प्रयास किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक देव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हमारे एयरपोर्ट से इस माह दो विमान सेवा प्रारंभ की जा रही हैं, जो क्षेत्र के विकास, पर्यटन, व्यापार के लिए लाभप्रद होगा। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बस्तर से यह सेवा शुरू की है। जगदलपुर-दिल्ली सेक्टर को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में शामिल किया है। आने वाले तीन साल तक बस्तर के यात्री रियायती दर पर इस रूट पर यात्रा कर पाएंगे। लंबे वक्त से बस्तर से दिल्ली की फ्लाइट शुरू करने की मांग की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। बस्तर के लिए यह बड़ी सौगात है।

# एसीआई के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग में स्थापित हुई 6 नई मशीन

■ स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन

**रायपुर।** पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध डॉ। भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एसीआई के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग को आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने हृदय, फेफड़े और संवहनी तंत्र (सर्कुलेटरी सिस्टम) से जुड़े रोगों के उपचार के लिए छह अत्याधुनिक उपकरण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अंतर्गत उपलब्ध कराए है। मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग में स्थापित इन अत्याधुनिक उपकरणों का विधिवत् उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरन्दर

मिश्रा, विधायक रायपुर ग्रामीण मोतीलाल साहू, कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा जनक प्रसाद पाठक, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ। विष्णु दत्त, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय डॉ। तृप्ति नागरिया, अधीक्षक डॉ। एस। बी। एस। नेताम, पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ। अरविंद नेरल, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ। स्मित श्रीवास्तव, सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ। कृष्णकांत साहू समेत आईसीआईसीआई फाउंडेशन के जोनल हेड विवेकानंद दुबे मौजूद रहे।

# छत्तीसगढ़ कोल लेवी स्कैम में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को झटका

## बिलासपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ का कोयला लेवी घोटाले में फंसे विधायक देवेंद्र यादव को राहत नहीं मिल रही है। हजारों रुपये के इस कथित घोटाले में भिलाई नगर से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी बेल पीटिशन को खारिज कर दिया। 2 हजार करोड़ से अधिक के कोल लेवी स्कैम में ईडी ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया है। इस पर देवेंद्र यादव ने गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है।

इससे पहले देवेंद्र यादव की याचिका

रायपुर की स्पेशल कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। निचली अदालत ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का खर्च उन्होंने चुनाव में किया था। निचली अदालत के फैसले के बाद देवेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन मंगलवार को आए फैसले में उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया।

ईडी ने कोल लेवी स्कैम में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ आरोप लगाए हैं। देवेंद्र यादव के खिलाफ जांच भी की गई है। ईडी का दावा है कि देवेंद्र यादव के ठिकानों पर छापेमार कर्रवाई के दौरान उन्हें कई सबूत मिले हैं। अब इस केस में राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो भी जांच कर रही है। करीब 105 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। कोल लेवी स्कैम में सौम्या चौरसिया, रानू साहू और समीर बिश्नोई के नाम भी शामिल हैं। तीनों आईएएस अधिकारी जेल में हैं।

ईडी ने छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ के कोयला लेवी घोटाले का खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक कोयले के परिवहन को लेकर अधिकारियों, कारोबारियों और राजनेताओं का एक कार्टेल बनाया गया था। जो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रति टन 25 रुपये की वसूली करता था। इस तरह कोयले के परिवहन से यह घोटाला किया गया।

# कांकेर में देर रात मंत्री बृजमोहन ने ली बैठक

■ रायपुर लोकसभा चुनाव में जीत का दावा, कहा- दिल्ली से पूरे प्रदेश पर रखेंगे नजर

**कांकेर।** छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सोमवार को पहली बार कांकेर पहुंचे। देर रात पहुंचे मंत्री ने जिला पंचायत सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली जो देर रात तक साढ़े 12 बजे तक चली। इस दौरान विभिन्न विभागों में हो रहे विकास कार्यो में देरी को लेकर कई अधिकारियों को मंत्री ने फटकार भी लगाई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी और विभाग की जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं। उनका हितग्राहियों को लाभ मिले इस बात की समीक्षा की गई है।

अग्रवाल ने कहा जो अधिकारी मीटिंग में नहीं आए उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया। जो तैयारी से नहीं आए उन्हें आगे पूरी तैयारी से आने को कहा गया है।

देर रात तक बैठक लेने के बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीटिंग के बारे में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा

कि पहली बार देर रात तक बैठक नहीं हुई है। इससे पहले भी सुबह 4 बजे तक बैठक हुई है। समीक्षा बैठक में मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव साय की गारंटी, प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, सबके खाते में दो साल के बोनस की राशि, महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं को मिले, डीएमएफ के पैसों का सदुपयोग हो, इस बात की समीक्षा की गई है। रिजल्ट ओरियेंटेड काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

किसान सम्मान निधि को लेकर मंत्री ने कहा कि- कांकेर संवेदनशील क्षेत्र है इसलिए बैंक में एक साथ ज्यादा पैसा नहीं रखा जा सकता। बैंक के मोबाइल यूनिट के जरिए जो किसान बैंक में अपने पे स्लिप देता है तो उसके जरिए भी किसानों को सम्मान निधि दी जाएगी।

जल जीवन मिशन को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने बताया-पहले से ही जल जीवन मिशन का काम 3 साल देर हो चुका है। इस साल की गर्मी से पहले किसी गांव में पानी की समस्या नहीं होगी। जलजीवन मिशन के काम को लेकर पूरा करने का समय है तो ट्यूबवेल कर उसमें मोटर लगाकर टंकी लगाकर गांव वालों को पानी देना सुनिश्चित किया गया है। 30 मार्च तक हर गांव में पानी का स्रोत ढूंढकर मोटर लगाकर ग्रामीणों को पानी उपलब्ध करने को कहा गया है।

रायपुर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पहले रायपुर से राज्य को देखते थे अब दिल्ली से पूरे प्रदेश को देखेंगे। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 में रायपुर सीट से भाजपा ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को खड़ा किया है।

## रायपुर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी ड्राइवर को आया हार्ट अटैक

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के बाहर एक टैक्सी ड्राइवर की अचानक तबीयत खराब हो गई। वहीं अस्पताल के सामाने टैक्सी ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन समेत वहां मौजूद टैक्सी ड्राइवरों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके साथ ही परिजन और ड्राइवरों ने मुवावजा की मांग की है। यह मामला बीते दिनों सोमवार दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे की है। सरायपाली से ड्राइवर उमा शंकर पटेल रायपुर एयरपोर्ट अपने पैसेंजर को लेने पहुंचा था। उमाशंकर एयरपोर्ट के बाहर अपने पैसेंजर का इंतजार कर रहा था। इस दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिलने से मौके पर टैक्सी ड्राइवर्स ने उपचार के लिए उसे माना स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। टैक्सी ड्राइवरों और परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल पहुंचने के बाद 20 मिनट तक बाहर कार में ही उमाशंकर को रखा गया।

**कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक**
**डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर (छ.ग.)**

क्रमांक / डॉ.भी.अ.चि./क्रय/ 2024/4985 रायपुर, दिनांक 07/03/2024

**'ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम निविदा आमंत्रण सूचना'**

डॉ.भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के विभिन्न विभागों से संबंधित दवाईयां, इम्प्लांट एवं सामग्री क्रय हेतु निम्नानुसार ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की गई है। इसका विस्तृत विवरण वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in पर सिस्टम टेण्डर क्रमांक 153675, 153777, 153776, 153775 में देखा जा सकता हैं।

| DETAIL | BID SUBMISSION START DATE | BID DUE DATE | PHYSICAL FDR SUBMISSION END DATE |
|---|---|---|---|
| 153675 ORTHO IMPLANT | 13 MAR, 2024 05:30:49 PM IST | 15 APR, 2024 12:00:00 PM IST | 15 APR, 2024 12:30:00 PM IST |
| 153777 LOCAL PURCHASE | 13 MAR, 2024 05:30:49 PM IST | 15 APR, 2024 12:00:00 PM IST | 15 APR, 2024 12:30:00 PM IST |
| 153776 EYE DEPT. MEDI./CONSUMABLES | 13 MAR, 2024 05:30:49 PM IST | 16 APR, 2024 12:00:00 PM IST | 16 APR, 2024 12:30:00 PM IST |
| 153775 GENERAL MEDICINE/ CONSUMABLES | 13 MAR, 2024 05:30:49 PM IST | 16 APR, 2024 12:00:00 PM IST | 16 APR, 2024 12:30:00 PM IST |

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर ( छ. ग. )

जी-08420/4

# रूस-यूक्रेन, इस्राइल-गाजा की जंग, दो युद्धों से सबक ले भारत

**हर्ष वी. पंत**

युद्ध लड़ना अपने आप में घृणित काम है। यह अपने साथ जो राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक गिरावट लाता है, उसे समझना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है, जो उसे दूर से देख रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए युद्ध महज एक ऑडियो-विजुअल एक्सपीरिएंस होता है जिसे अक्सर वे उसके राजनीतिक और सामरिक संदर्भों से अलग, मनोरंजन के एक साधन के रूप में लेते है। विकसित देशों के एक बड़े हिस्से के साथ अभी हाल तक यही बात लागू होती थी। उसे लगता था कि युद्ध सुदूर इलाकों में ही लड़े जाते हैं, जिनका उसकी रोजाना की जिंदगी से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं होता। इस हिस्से के लिए मौजूदा दौर हकीकत का एक नया अहसास लेकर आया है। अभी यूरोप, यूक्रेन पर रूसी हमले की चुनौती से निपटने का सही तरीका खोजने की कोशिश में लगा है। जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां ने हाल में सुझाव दिया कि यूक्रेन में सेना भेजने पर आम सहमति भले न बनी हो, लेकिन कोई भी विकल्प छोड़ा नहीं जाना चाहिए तो इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, न केवल रूस की ओर से बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की ओर से भी। अमेरिका ने तत्काल साफ कर दिया कि जीत के लिए सैन्य सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। इसलिए यूक्रेनी सेना को वे सारे हथियार और गोले बारूद मुहैया कराए जाते रहेंगे, जो उसे बचाव करने के लिए चाहिए। लेकिन 'अमेरिका यूक्रेन में लड़ने के लिए अपनी सेना नहीं भेजने जा रहा।' ब्रिटेन ने कहा कि उसके कुछ सैनिक पहले से ही यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो यूक्रेन में सैन्य तैनाती की उसकी कोई योजना नहीं है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने भी दोहराया कि कोई भी यूरोपीय देश या नैटो सदस्य देश यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। यूक्रेन युद्ध में यह एक नाजुक पल है जब दो साल की भीषण लड़ाई के बाद मैदान में रूस का पलड़ा भारी लग रहा है। पिछले कुछ सप्ताह में उसे कुछ बढ़त हासिल हुई है, हालांकि इस बढ़त के मायनों पर आम राय नहीं है। पूतिन को लग रहा है कि अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण और यूरोपीय देशों में जनता के असंतोष को देखते हुए उन्हें सिर्फ थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। दूसरी तरफ पश्चिम अभी भी ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश ही कर रहा है, जो विश्वसनीय ढंग से यह संदेश दे सके कि वह यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा, भले ही आर्थिक और राजनीतिक लागत बढ़ जाए। कुछ ही दिन पहले हंगरी ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल का यूक्रेन के लिए 'अडिग' समर्थन का वादा करने वाला एक बयान ब्लॉक कर दिया। ऐसे में मैक्रां का यह कहना मायने नहीं रखता कि 'रूस का हारना यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता के लिहाज से जरूरी है।' यह स्पष्ट नहीं है कि पश्चिम के पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त साधन हैं या नहीं। मगर रूस के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह खुद अपने संसाधनों के बल पर यह युद्ध लड़ रहा है। दूसरा युद्ध जो मध्य पूर्व में चल रहा है, उसमें भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इस दावे के बावजूद कोई हल निकलता नहीं दिख रहा कि उन्हें अगले सप्ताह तक युद्धविराम होने की उम्मीद है। यह युद्ध तब शुरू हुआ, जब पिछले अक्टूबर में हमास के आतंकी हमले में करीब 1,200 लोगों के मारे जाने के बाद इस्राइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए। अब स्थिति यह है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस्राइली कार्रवाई से उत्पन्न मानवीय संकट पर टिका है। इस्राइली सेना की रणनीति को लेकर शुरू से विवाद रहा है। उसकी कार्रवाई ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। वह हमास को कुछ प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाने में भी सफल रहा है। लेकिन नेतन्याहू सरकार गाजा के भविष्य के मद्देनजर शासन और पुनर्निर्माण की कोई वास्तविक सुसंगत योजना पेश नहीं कर सकी है। इस्राइल सीरिया, इराक और यमन में हमास, हिजबुल्ला और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स के हमलों से जूझ रहा है। वह एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जाहिर है, ऐसे में तनाव बढ़ने और युद्ध फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है।

# कांग्रेस के पास नहीं है मोदी की काट

**कृष्णमोहन झा**

कुछ सप्ताह पूर्व जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि कमलनाथ ने नेहरू गांधी परिवार के साथ अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था अत: उनके भाजपा में शामिल होने की बात आप सोच भी कैसे सकते हैं। बाद में स्वयं कमलनाथ ने सारी अटकलों को खारिज कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने राहत की सांस ली। कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा महसूस हुआ कि लोकसभा चुनावों की घोषणा के पहले एक बड़ा संकट पार्टी के सिर से टल गया लेकिन गत दिवस अब अचानक ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार बार के राज्य सभा सांसद सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की खबर सामने आई तो मुझे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कमलनाथ के बारे में कही गई यह बात याद आ गई कि कोई ऐकासा सोच भी कैसे सकता है।

कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तो क ई दिनों से लगाई जा रही थीं इसलिए कांग्रेस पार्टी को उन्हें मनाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया परंतु जब सुरेश पचौरी भाजपा में शामिल हुए तो कांग्रेस पार्टी को मान मनौव्वल का मौका ही नहीं मिल पाया। आज कांग्रेस नेतृत्व यह सोच सोच कर हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हों तब नि:संदेह कांग्रेस पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। गौरतलब बात यह भी है सुरेश पचौरी के साथ ही पूर्व सांसद गजेन्द्र सिंह राजू खेड़ी , पूर्व विधायक संजय शुक्ला, भोपाल नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मिश्र सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है इन सभी नेताओं का भोपाल स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पुष्पहार और अंगवस्त्र पहना कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र सहित भाजपा के अनेक नेता मौजूद थे।

भाजपा ने सुरेश पचौरी का स्वागत जिस तरह पलक पांवड़े बिछाकर किया है उससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। सौंपी जा सकती है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके अंदर संत कहे जाने वाले राजनेता ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी विचार धारा अलग थी परन्तु मैं हमेशा उनकी शालीनता और शुचिता का कायल रहा। भाजपा में उनके शामिल होने के बाद राजनीति में उनके अनुभव हमारे काम आएंगे। सुरेश पचौरी ने कहा कि जब कांग्रेस ने अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकरा कर अनादर किया तो मुझे उसका बहुत आघात पहुंचा और मैंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला कर लिया। मैं भगवान राम का अनादर करने वालों के साथ नहीं चल सकता। सुरेश पचौरी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो पार्टी कभी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर का नारा लगाती थी वही पार्टी आज जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ी हो गई है इससे जातीय संघर्ष बढ़ रहा है।

लोकसभा चुनावों की घोषणा के कुछ ही दिन पहले मध्यप्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में प्रमुख सुरेश पचौरी का भाजपा में शामिल होने का फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है इसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया से समझा जा सकता है जो सुरेश पचौरी के इस फैसले से अत्यंत भावुक हो उठे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं -50 साल का रिश्ता भी कोई यूं तोड़ता है क्या। राम मंदिर में आस्था उचित है लेकिन राम की मर्यादा को न भूलें। सच का साथ देने के लिए संघर्ष के पथ पर निस्वार्थ भाव से चलना ही राम के प्रति सच्ची आस्था है। दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को यह याद दिलाने से भी नहीं चूके कि उन्हें जिस गांधी की बदौलत उन्होंने समाज में इतना मान - सम्मान कमाया उसका साथ संघर्ष के दिनों में उन्होंने छोड़ दिया। गौरतलब है कि सुरेश पचौरी अतीत में । मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव और अध्यक्ष,? मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के अलावा दो बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और चार बार राज्य सभा सांसद भी रहे चुके हैं।

सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के अंदर उन नेताओं की संख्या में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है जो आज की तारीख में यह मानने लगे हैं कि पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य अब सुरक्षित नहीं रह गया है। दरअसल कड़वी हकीकत यह है कि उन्हें समूची कांग्रेस पार्टी का ही भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद से अब तक कांग्रेस के 15 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों सहित अनेक वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। अभी हाल में ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हुए थे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की फेहरिस्त दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह निश्चित रूप से पार्टी के लिए चिंता का विषय है परन्तु अपने नेताओं में भाजपा के प्रति बढ़ते आकर्षण के लिए वह भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती । भाजपा के प्रति पार्टी के कुछ नेताओं के बढ़ते आकर्षण से न केवल कांग्रेस की चुनावी तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से पार्टी ने जो उम्मीदें लगा रखी हैं उन उम्मीदों पर भी पानी फिरता नजर आने लगा है। ऐसा न होता तो पार्टी से पलायन का सिलसिला अब तक थम गया होता।

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभाओं के चुनावों में कांग्रेस की शोचनीय पराजय ने पार्टी कार्यकर्ताओं ही नहीं वल्कि नेताओं का मनोबल तोड़ कर रख दिया है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कांग्रेस के कर्णधार इस कड़वी हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई लोकप्रिय को चुनौती देने का सामर्थ्य हो। प्रधानमंत्री मोदी के विराट व्यक्तित्व में समाया चुम्बकीय आकर्षण कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है और कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि उस चुंबकीय आकर्षण को निष्प्रभावी करने की ताकत कांग्रेस के किसी नेता में नहीं है। यही कारण है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को चुनौती देने की मंशा से विपक्षी दलों ने जो इंडिया गठबंधन बनाया था उसके घटक दलों को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए राजी करने में पार्टी असफल रही। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को भाजपा समर्थक हर राजनीतिक दल अपने सुनहरे भविष्य की गारंटी मान रहा है । मतदाताओं को भी मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। मोदी की गारंटी ही भाजपा के लिए लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

**भारतीय ज्ञान परंपरा....**

## महोपनिषद् (भाग-30)

**गतांक से आगे...**

बन्धन एवं मोक्ष के दो ही कारण बनते हैं, जिनमें प्रथम है- ममता एवं द्वितीय ममतारहित होना। ममता के द्वारा जीव बन्धन में पड़ता है और ममता से रहित हो जाने के पश्चात् वह (जीव) मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

जीव रूप एवं ईश्वररूप से ईक्षण अर्थात् ब्रह्म के संकल्प से प्रारम्भ होकर तथा ब्रह्म में प्रवेश के अन्त वाले इस सम्पूर्ण जड़-चेतनात्मक सृष्टि की कल्पना ईश्वर के द्वारा ही की गई है। जाग्रत् अवस्था से लेकर मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त सम्पूर्ण जगत् जीव के द्वारा ही कल्पित है। कठोपनिषद् के अन्तर्गत त्रिणाचिकेताग्नि से लेकर श्वेताश्वतर का योगपर्यन्त ज्ञान ईश्वरीय भ्रान्ति के आश्रित है।

चार्वाक मत से लेकर कपिल के सांख्यसिद्धान्त तक का दार्शनिक ज्ञान (सांख्य आदि दर्शनों में प्रतिपादित ज्ञान) जीव भ्रान्ति का आधार है। अत: जो पुरुष मुक्ति की आकांक्षा करता है, वह जीव तथा ईश्वर के वाद-विवाद में बुद्धि को भ्रमित न करे, वरन् उसे दृढ़तापूर्वक ब्रह्मतत्त्व का ही निरन्तर चिन्तन करना चाहिए।

ज्ञानवान् पुरुष वही है, जो सम्पूर्ण दृश्य-जगत् को निर्विशेष चित् रूप मानता हो। वही (कल्याणकारी) शिव है, वही ब्रह्मा एवं विष्णु भी वही है। विषय वासनाओं का त्याग अत्यन्त दुर्लभ है, तत्त्वज्ञान को प्राप्त करना भी अत्यन्त कठिन है और सद्?गुरु की अनुकम्पा के बिना सहजावस्था को प्राप्त करना भी अत्यधिक दु:साध्य है। जिसने अपनी बोधात्मिका शक्ति को जाग्रत् कर लिया है और अपने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, ऐसा योगी स्वयमेव सहजावस्था को प्राप्त कर लेता है; जब तक व्यक्ति को इसमें थोड़ा भी अन्तर मालूम पड़ता है, तब तक उसके लिए भय है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

**क्रमश: ...**

# भारत के प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खां

संगीत सीधे आत्मा से निकलता है और अच्छा संगीत बिना कहे अपनी बात दुनिया तक पहुंचाता है।' यह कहना था सितार वादन की दुनिया के बादशाह उस्ताद विलायत खां का। सितार वादन में अपना लोहा मनवाने वाले उस्ताद विलायत खां का जन्म तत्कालीन पूर्वी बंगाल के गौरीपुर में हुआ था। सितार वादन में उन्होंने अपनी एक अलग शैली विकसित की थी।

विलायत खां को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला था। उनके पिता इनायत हुसैन खां और उनके दादा उस्ताद इमदाद हुसैन खां भी प्रसिद्ध सितार वादक थे। विलायत खां के परिवार में पीढ़ियों से संगीत गूंजता रहा है। इस संगीत की गूंज विलायत खां में भी रची-बसी थी।

उस्ताद विलायत खां ने अपने संगीत घराने का नाम इटावा घराना रखा। उन्होंने सितार में गायकी अंग की शुरुआत की,

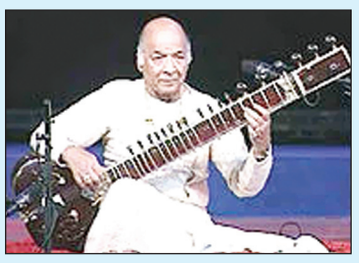

जिसमें वादन के साथ-साथ गायन भी शामिल था। वे अपना काम पूरी साधना से करते थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने संगीत वादन में ऐसे कीर्तिमान रचे, जिसे लोग आज भी नहीं कर पाते हैं।

विलायत खां ने अपना पहला संगीत कार्यक्रम कलकत्ता में ऑल बंगाल म्यूजिक कांफ्रेंस में दिया था। 1950 के दशक में विलायत खां ने संगीत के साजो-सामान बनाने वाले निर्माताओं के साथ भी काम किया। अमूमन वे तानपुरा के साथ प्रस्तुति नहीं देते थे। अपने समय में उन्होंने कई रागों की व्याख्या की और कई राग खुद रचे।

अपनी कला में प्रयोगधर्मी रहे उस्ताद विलायत खां ने कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में भी संगीत दिया था। उन्होंने 1958 में बनी सत्यजित राय की बांग्ला फिल्म 'जलसाघर' (1969), मर्चेंट आइवरी की फिल्म 'द गुरु' और 1976 में मधुसूदन कुमार की हिंदी फिल्म 'कादंबरी' में संगीत दिया था।

विलायत खां को मिले पद्म सम्मानों को लेकर विवाद भी उठे। उन्हें 1964 और 1968 में क्रमश: पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए कि भारत सरकार ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान का सम्मान नहीं किया, दोनों पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। एक साक्षात्कार में विलायत खां के बेटे शुजात खां ने कहा कि 'एक ऐसा कलाकार, जो इतनी पीढ़ियों की विरासत को न सिर्फ संभाल कर चल रहा हो, बल्कि उसमें बहुत कुछ जोड़ भी रहा हो, नाराज हो ही जाता है, जब उसका देश उसकी काबिलियत को नजरअंदाज कर दे।' सन 2000 में उन्हें दूसरी बार पद्म विभूषण दिया गया, लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार को भी अपना 'अपमान' कहते हुए लेने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अगर कोई अवॉर्ड मेरे शागिर्द या जूनियर को बीते साल दिया जा चुका है, वह मुझे अब क्यों दिया जा रहा है?

वे फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज मुंबई के जसलोक अस्पताल में चला, जहां उनका 13 मार्च, 2004 में निधन हो गया।

# संयुक्त राष्ट्र के बारे में भारत की चिंता जायज

**राजेश बादल**

एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के कामकाज और उसके स्वरूप में बदलाव पर भारत ने जोर दिया है। पहली बार उसने गंभीर चेतावनी भी दी है। इससे पहले उसने अनेक अवसरों पर शिखर संस्था में बदलाव और उसके मौजूदा रवैये पर समूचे का ध्यान खींचा है। लेकिन, विकसित सदस्य देशों ने कभी उसकी बात पर गौर नहीं किया। इस बार हिंदुस्तान के सुर बेहद अलग अंदाज में निकले।

संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब यदि संयुक्त राष्ट्र में सुधार नहीं किए गए तो यह संस्था गुमनामी में खो जाएगी। संगठन खतरे में पड़ जाएगा और विश्व के विकासशील देश वैकल्पिक राह चुनने के लिए आजाद होंगे। यह स्थिति अच्छी नहीं है और संकेत करती है कि जिस उद्देश्य से इस वैश्विक संस्थान का गठन किया गया था, वह पूरा नहीं हो रहा है। छोटे-बड़े मुल्कों में गहन असंतोष है।

अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में यह आर्गेनाइजेशन चंद देशों की जेब में जाकर बैठ जाएगा। उन्होंने आगाह किया कि अब भारत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत की इस चेतावनी को कुछ बड़े राष्ट्रों का समर्थन तो मिला है, मगर कहा नहीं जा सकता कि यह समर्थन कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। मसलन ब्रिटेन ने भारत से सहमति जताई और स्वीकार किया कि वीटो पॉवर ही सुधार के रास्ते में असली बाधा है।

इसके अलावा समूह-चार के ब्राजील, जापान और जर्मनी ने भी भारत की बात से सहमति प्रकट की। ये देश पिछले साल भी भारत के विदेश मंत्री की राय से भी सहमत थे कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वांछित सुधार नहीं हुए तो सदस्य देश बाहरी समाधान खोजने लगेंगे। यह बूढ़ों के क्लब जैसा हो गया है। पांच देश नहीं चाहते कि उन पर कोई उंगली उठाए अथवा उनके मामलों में टांग अड़ाए।

समझना होगा कि भारत ही संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में परिवर्तन पर इतना जोर क्यों दे रहा है. तमाम राष्ट्रों के भीतर चिंता का यह आकार छोटा क्यों है? आपको याद होगा कि सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पचपन साल पूरे होने पर वैश्विक समारोह हुआ था। इसमें कमोबेश सारी दुनिया के राजनेताओं ने शिरकत की थी। इस जलसे में एक संकल्प लिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यशैली में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। पर, कुछ नहीं हुआ। सारा संकल्प ठंडे बस्ते में बंद होकर रह गया।

अब छह महीने बाद सितंबर में इस संस्था के अस्सी साल पूरे हो जाएंगे तो एक बार फिर भव्य समारोह की तैयारी चल रही है। इसमें भी इन सुधारों का मामला उठेगा। भारत का कहना है कि संसार की सत्रह फीसदी आबादी भारत में रहती है। सुरक्षा परिषद के चार सदस्य रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत की स्थायी सदस्यता के पक्षधर हैं। सिर्फ चीन भारत के खिलाफ है। वह अपने निजी हितों के चलते इतने बड़े मुल्क की उपेक्षा कर रहा है। अब चीन की दादागीरी से अन्य चार सदस्य भी परेशान हो चुके हैं।

वैसे भारत के पक्ष में एक बात और भी है। संयुक्त राष्ट्र में उसकी आवाज लगातार मजबूत होती गई है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध सभी राष्ट्रों के बीच भारत की साख हमेशा बेहतर रही है। जब-जब भी अस्थायी सदस्यता के लिए मतदान हुआ, भारत को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे। सन 1950 में कुल 58 वोटों में से भारत को 56 वोट मिले थे। इसके बाद 1967 में भारत को कुल 119 में से 82 मत हासिल हुए।

हालांकि, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे थे। यह अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति थी। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता के शिखर पर थीं। उन्होंने दुनिया के नक़्शे में बांग्लादेश नाम के नए देश को जन्म दिया था तो उसके अगले साल यानी 1972 में 116 में से 107 देश भारत के साथ खड़े थे। यानी भारत अपनी प्रतिष्ठा के मान से फिर विश्व बिरादरी में शिखर पर था। अगले पांच साल बाद भी ऐसी स्थिति बनी रही।

जब 1977 में मतदान हुआ तो कुल 138 देशों में से 132 मुल्कों का वोट भारत को मिला था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष देश एकजुट थे इसलिए उसका लाभ भारत को मिलता रहा। उसके बाद के दस बरस भी हिंदुस्तान की लोकप्रियता के नजरिए से सुनहरे थे। इंदिरा गांधी और उनके बाद राजीव गांधी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उभरे। उस साल भारत को 155 में से 142 राष्ट्रों का साथ मिला।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सन् 2011 -12 में डॉ. मनमोहन सिंह के जमाने में ग्राफ सबसे ऊपर रहा। कुल 191 में से 187 देशों का साथ हिंदुस्तान को मिला। पिछला चुनाव 2021-22 में हुआ था। उस समय तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे। उस दरम्यान 192 में से 184 राष्ट्रों ने भारत के पक्ष में मतदान किया था।

इस तरह आठ बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने का अवसर हिंदुस्तान को मिला है। भारत की शानदार छबि के बाद भी चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे देखते हुए भारत का आक्रोश और सवाल जायज है कि संसार की इस सबसे बड़ी पंचायत पर काबिज देश आखिर कब तक हिंदुस्तान की उपेक्षा करते रहेंगे? उसके बड़े संवेदनशील निर्णयों में भारत की भागीदारी कब और कैसे होगी?

## आज का इतिहास

1897 सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी।
1920 कप्प पुट्स ने वीमार गणराज्य सरकारफ़ॉम बर्लिन को कुछ समय के लिए हटा दिया।
1943 होलोकॉस्ट-नाज़ी जर्मन सैनिकों ने पोलैंड के क्राकोव में यहूदीगेटो को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे प्लाज़्ज़ो लेबर कैंप (निर्वासित चित्र) पर काम करने में सक्षम लगभग 8000 यहूदियों को भेजा गया, बाकी को या तो अटैक किया गया या औशविट्ज़ को भेजा गया।
1943 प्रलय: नाजी जर्मन सैनिकों ने पोलैंड के क्राकोव में यहूदी यहूदी बस्ती को नष्ट करना शुरू कर दिया, लगभग 8, 000 यहूदियों ने प्लाज़्ज़ो श्रम शिविर में काम करने में सक्षम माना, बाकी या तो मारे गए या औशविट्ज़ को भेजे गए।
1944 इटली और सोवियत संघ ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंध दुबारा बहाल किए।
1961 ब्रिटेन की दो महिला और तीन पुरुष अधिकारियों पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था। कहा गया था कि वो देश के सुराग रूस भेज रहे थे।
1961 भूस्खलन से सोवियत संघ में 145 लोगों की मौत हुई।
1962 अमेरिका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष लिमन लेमनगिटेरडिलीवर ने रक्षा के सचिव रॉबर्ट मैकनामारा के एक प्रस्ताव का आह्वान किया, जो फिडेलकैस्ट्रो और क्यूबा के खिलाफ युद्ध के लिए सार्वजनिक समर्थन बनाने के लिए ऑपेरशन नॉर्थवुड्स है, जिसे अंतत: राष्ट्रपति जॉन एफ.केनेडी ने अस्वीकार कर दिया था।
1963 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई।
1986 निर्दोष मार्ग के अधिकार का दावा करते हुए, अमेरिकी युद्धपोतों यूएसएस यॉर्कटाउन और यूएसएस कैरन ने सोवियत युद्ध की तत्परता को भड़काते हुए काला सागर में सोवियत प्रादेशिक जल में प्रवेश किया।
1988 दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग सीकन टनल, जापान के हाकोडेट और अओमोरी शहरों के बीच खोली गई।
1996 स्कॉटलैंड के डनब्लेन के स्कूल में एक बंदूकधारी ने घुसकर गोलियों की बौछार कर दी जिसमें 16 बच्चे और उनके शिक्षक की मौत हो गई।
1996 थॉमस हैमिल्टन ने 16 किंडरगार्टन, उनके शिक्षक और खुद को मार डाला।
1996 यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में बच्चों पर हुए सबसे जानलेवा हमले में, स्कॉटलैंड के डनब्लेन में एक प्राथमिक स्कूल में एक हत्यारे ने सोलह बच्चों और एक शिक्षक की हत्या कर दी।
1999 शेख़ हमाज बिन ईसा अल ख़लीफ़ा बहरीन के नये शासक बने।
2002 राबर्ट मुगावे पुन: जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
2008 नासा का अंतरिक्ष यान एंडेवर सकुशल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँचा।
2011 बिजली संयंत्र से परमाणु संदूषण के डर के कारण, 200,000 से अधिक लोगों को जापान से निकाला गया था।
2011 जापान के 9.0 भूकंप में 46,000 से अधिक संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं।
2012 बंगलादेश की राजधानी ढाका के समीप एक तेल टैंकर और एक नौका के बीच हुई टक्कर में 110 लोगों की मौत हुई।
2012 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि लाल मांस से मृत्यु बढ़ जाती है और इसके अतिरिक्त नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव हैं।
2012 25 साल का अलास्कन, डलास सीवे, इडिट्रॉड ट्रेल स्लेज डॉग रेस का सबसे कम उम्र का विजेता बन जाता है।

# मध्य प्रदेश में मोहब्बत की दुकान छोड़कर क्यों भाग रहे कांग्रेसी?

**सिद्धार्थ शंकर गौतम**

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देशभर में %नफरत के बाजार में, मोहब्बत की दुकान% खोलने का उपक्रम कर रहे हैं किंतु मध्य प्रदेश में उनकी मोहब्बत की दुकान में ताला लगने की नौबत आती जा रही है। कमलनाथ के भगवाधारी होने-न होने के अंदेशे के बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से रुखसती के तीसरे दिन इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेताओं में शुमार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेश पचौरी ने अपने समर्थक दल-बल के साथ कांग्रेस को बाय-बाय कह दिया।

सुरेश पचौरी के साथ इंदौर लोकसभा क्षेत्र से संजय शुक्ला और देपालपुर से विशाल पटेल सहित भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, धार से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी व अन्य ने कांग्रेस को 2020 की ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सबसे बड़ा झटका दिया है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सामने विधानसभा चुनाव लड़ने से देशभर में चर्चा के केंद्र में आए संजय शुक्ला का नाम इंदौर लोकसभा से कांग्रेस के पैनल में सबसे ऊपर था, वहीं सुरेश पचौरी को भी पार्टी भोपाल या होशंगाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ाने के मूड में थी। किस्मत तो गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी की भी चमक सकती थी क्योंकि धार से कांग्रेस को कोई सशक्त चेहरा नहीं मिल रहा था। अब स्थिति यह है कि इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद और धार से कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो भाजपा के मजबूत प्रत्याशी के सामने लड़ सके।

सूत्रों के अनुसार धार से गजेंद्र सिंह तो होशंगाबाद से सुरेश पचौरी भाजपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि भाजपा ने होशंगाबाद लोकसभा सीट से दर्शन सिंह चौधरी को टिकट दे दिया है किंतु पार्टी यहां बदलाव भी कर सकती है। यदि टिकट न भी बदला तो 24 वर्षों तक राज्यसभा सांसद रहे सुरेश पचौरी को पार्टी राज्यसभा में एडजस्ट कर उनके अनुभव का लाभ उठा सकती है। हालांकि अब भाजपाई हलकों में यह प्रश्न मुखर होता जा रहा है कि वर्तमान भाजपा तो पहले से अधिक कांग्रेसी होती जा रही है। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? क्या भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता इन आयातित नेताओं को दिल से स्वीकार कर पाएंगे? इन सबमें यह भी बड़ा प्रश्न है कि इन सभी नेताओं का पुनर्वास कैसे और कब होगा?

राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश आगमन के समय ग्वालियर-चंबल संभाग में कार्यकर्ताओं के नाश्ते-भोजन की व्यवस्था का अपने खर्चे पर प्रबंध करने वाले संजय शुक्ला 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। पार्षद, विधायक रहते हुए अपने खर्च से क्षेत्र की जनता को तीर्थयात्रा करवाने और भंडारे की राजनीति से इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के समकक्ष खड़े होने से संजय शुक्ला कांग्रेस के कद्दावर नेता बन गए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके बढ़ते कद को देखते हुए भाजपा ने अपने कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को संजय शुक्ला के सामने इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से उतारकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इंदौर में जनसंघ और भाजपा के शिल्पकार रहे स्व. विष्णुप्रसाद शुक्ला के बेटे संजय शुक्ला को पूरे चुनाव प्रचार में कैलाश विजयवर्गीय अपना बच्चा बताते रहे किंतु संजय शुक्ला ने उन पर गंभीर एवं चारित्रिक आरोपों की झड़ी लगा दी।

हालांकि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीत गए किंतु

इंदौर शहर की जनता के मन में यह बात घर कर गई कि भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो वह संजय शुक्ला ही है। अब जबकि संजय शुक्ला स्वयं कैलाश विजयवर्गीय के हाथों से भगवा गमछा पहन चुके हैं तो इंदौर की राजनीति के समीकरण ही बदल गए हैं। समीकरण तो शुक्ला परिवार में भी बदलेंगे क्योंकि इन्हीं संजय शुक्ला के चचेरे भाई गोलू शुक्ला कांग्रेस के गढ़ रहे विधानसभा क्रमांक 3 से कमल खिला चुके हैं। अब एक ही परिवार के दो कद्दावर भाइयों की राजनीतिक उड़ान को भाजपा कितनी ढील देगी, यह भविष्य बताएगा। इसी प्रकार देपालपुर से धनाढ्य विशाल पटेल को भाजपा में शामिल करवाकर पार्टी ने स्व. निर्भयसिंह पटेल की राजनीतिक विरासत के भी दो टुकड़े कर दिए हैं जिसका दूसरा टुकड़ा विधायक मनोज पटेल होंगे। विशाल और मनोज की राजनीतिक अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के वरदहस्त के चलते मनोज पटेल अब तक विशाल पटेल से जमकर लोहा लेते थे किंतु अब न तो प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज है और न ही उनका हस्तक्षेप वर्तमान शासन बर्दाश्त करेगा। ऐसे में विशाल पटेल के भाजपा में आने और संजय शुक्ला के मित्र होने का लाभ तो उनको मिलेगा।

जहां तक सुरेश पचौरी की बात है तो वे कभी जननेता नहीं रहे। यहां तक कि अपने जीवन में दो चुनाव, लोकसभा और विधानसभा, वे बुरी तरह हारे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए उन पर टिकट के बदले धन लेने के भी आरोप लगे थे किंतु गांधी-नेहरू परिवार से नजदीकी उनको बचा ले गई। हालांकि यह भी सच है कि प्रदेश में कांग्रेस की सर्वाधिक दुर्गति भी उन्हीं के अध्यक्ष रहते हुई। उन्हें कांग्रेस ने हमेशा ब्राह्मण नेता के तौर पर प्रस्तुत किया है किंतु वे कभी प्रदेश के ब्राह्मणों के नेता नहीं बन पाए। भाजपा ने पचौरी का आगमन मात्र कांग्रेस का मनोबल तोड़ने हेतु किया है ताकि यह संदेश दिया जा सके कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में स्वयं को असहज महसूस कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के भाजपा में आने से धार में रंजना बघेल परिवार को परेशान होना स्वाभाविक है क्योंकि अब तक परिवार के नखरे झेलती रही भाजपा में अब एक सशक्त चहेरा है जो धार में पार्टी की राजनीति को धार दे सकता है।

भोपाल से कैलाश मिश्रा का हित सुरेश पचौरी तय करेंगे क्योंकि राजधानी में भाजपा में एक अनार सौ बीमार वाले हाल हैं और कई कद्दावर नेता पद की लालसा में पार्टी की ओर ताक रहे हैं। खैर, ये सभी तो देर-सवेर कुछ न कुछ पा ही लेंगे किंतु खोया तो जनता का विश्वास है कि जो एक-दूसरे के खिलाफ खड़े थे, आज साथ साथ खड़े हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने राहुल गांधी के करीबी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का मुखिया यह सोचकर बनाया था कि वे वरिष्ठ एवं युवा नेताओं के बीच समन्वय स्थापित कर पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे किंतु उनके अध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी नेताओं में अजीब सी बेचैनी दिख रही है। वरिष्ठ उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं तो युवाओं को उनका बॉस रूप अधिक पसंद नहीं आ रहा।

स्थिति यह हो गई है कि इंदौर के होने के बाद भी उन्हें इंदौर के दो बड़े कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने की भनक तक नहीं लगी। यदि यही हाल रहा तो नकुलनाथ भी यदि भगवा गमछा ओढ़े दिखें, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह तो पहले से ही पार्टी को आंखें दिखाने लगे थे। भाजपा अरुण यादव पर भी डोरे डाल रही है। अभी स्थिति यह है कि कांग्रेसी प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें जीतने और 6 पर कड़ी टक्कर देने का दंभ भर रहे हैं किंतु लड़कर जीतेगा कौन, इस पर मौन साधे हुए हैं। कई लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास मजबूत और सर्वमान्य चेहरा तक नहीं है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर जैसे महानगरों में दशकों से कांग्रेस का सांसद नहीं बना है। इन परिस्थितियों में मोहब्बत की दुकान खोलने से अच्छा होता कि राहुल गांधी पहले मोहब्बत बेचने वाले दुकानदारों को संभालते ताकि मोहब्बत खरीदने वाले खरीददार तो मिलते। फिलहाल तो मोहब्बत की दुकान में कुछ ही लोग बचे हैं और जो बचे हैं वे साहूकार हैं जिनके पास खरीददार जाना नहीं चाहते।

# लोकसभा चुनाव के झरोखे से सुकुमार सेन और टीएन शेषन की यादें

**आरके सिन्हा**

एक बार फिर से देश लोकसभा चुनावों के लिए तैयार है। लोकसभा चुनावों को सफलतापूर्वक करवाने की जिम्मेदारी डेढ़ करोड़ सरकारी अफसरों पर होगी। करीब सवा करोड़ मतदान केंद्रों में जाकर मतदाता देश के 543 लोकसभा सांसदों का चुनाव करेंगे। बहरहाल, भारत में अब तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। पहली लोकसभा के चुनाव 25 अक्तूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए थे। उस समय लोकसभा में कुल 489 सीटें थीं लेकिन संसदीय क्षेत्रों की संख्या 401 थी। लोकसभा की 314 संसदीय सीटें ऐसी थीं, जहां से सिर्फ एक-एक

प्रतिनिधि चुने जाने थे। वहीं 86 संसदीय सीटें ऐसी थीं जिनमें दो-दो लोगों को सांसद चुना जाना था। वहीं नॉर्थ बंगाल संसदीय क्षेत्र से तीन सांसद चुने गए थे। किसी संसदीय क्षेत्र में एक से अधिक सदस्य चुनने की यह व्यवस्था 1957 तक जारी रही। पहले आम चुनाव में 21 या उससे अधिक उम्र के करीब 18 करोड़ मतदाता थे पूरे देश में। इनमें से लगभग 85 प्रतिशत पढ़ या लिख नहीं सकते थे। प्रत्येक मतदाता की पहचान और पंजीकरण किया जाना था फिर मतदान केंद्रों को उचित दूरी पर बनाया जाना था और ईमानदार व कुशल मतदान अधिकारियों की भर्ती की जानी थी। यह सब काम सुकुमार सेन के नेतृत्व में चुनाव आयोग कर रहा था। इस बीच, 24 फरवरी और 14 मार्च 1957 के बीच हुए दूसरे चुनाव के दौरान भी सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहे। यह मानना होगा कि पहले चुनाव आयुक्त के रूप में जिस परंपरा को सुकुमार सेन ने शुरू किया था, उसे आगे लेकर जाने वाले कुशल चुनाव आयुक्तों में टी.एन.शेषन ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1990 के दशक में चुनाव आयोग के प्रमुख पद पर रहते हुए चुनाव सुधारों को सख्ती से लागू करने का अभियान शुरु किया। शेषन ने अपने साथियों में यह विश्वास जगाया कि उन्हें चुनाव की सारी प्रक्रिया को ईमानदारी से अंजाम देना चाहिए। उनसे पहले के कुछ चुनाव आयुक्तों पर आरोप लगते रहते थे कि वे पूरी तरह से सरकार के इशारों पर ही चुनाव करवाते थे। शेषन ने साबित किया था कि सिस्टम में रहते हुए भी बहुत कुछ सकारात्मक किया जा सकता है। वे अपने दफ्तर में बैठकर काम करने वाले अफसर नहीं थे। शेषन चाहते थे कि चुनाव सुधार करके भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। शेषन ने अपने लिए एक कठिन और कठोर राह को पकड़ा। उन्होंने चुनाव सुधार का ऐतिहासिक कार्य करके विश्व भर में नाम कमाया। उन्होंने देश को जगाने के उद्देश्य से 1994 से 1996 के बीच चुनाव सुधारों पर देश भर में सैकड़ों जन सभाओं को भी संबोधित । अब जबकि देश आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार है तो सुकुमार सेन जी और टी.एन. शेषन का स्मरण जरूरी हो गया है।

# भाजपा का चुनावी दांव है नागरिकता संशोधन कानून

**अजय सेतिया**

मोदी सरकार ने अपना वायदा निभाते हुए नागरिकता संशोधन क़ानून के नियम जारी कर दिए हैं। विपक्ष, खासकर तृणमूल कांग्रेस, ऐसा मानकर चल रहे थे कि 2020 के नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ हुए मुस्लिम आन्दोलन से डर कर जैसे मोदी सरकार ने पिछले चार साल में सीएए के नियम लागू नहीं किए, वैसे ही चुनावों तक उसे ठंडे बस्ते में डाले रखेगी। इस क़ानून का मुस्लिमों की ओर से विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर सताए गए हिन्दुओं, सिखों, जैनियों, बोद्धों, पारसियों और ईसाईयों को क़ानून में ढील देकर भारत की नागरिकता दी जा रही है, वैसे ही बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जाए। जबकि भारत सरकार की नजर में बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, वहां मुसलमानों को धार्मिक आधार पर सताए जाने का कोई कारण ही नहीं है। जहां तक म्यांमार का सवाल है, तो वहां बांग्लादेशी मुसलमानों की हिंसक गतिविधियों के खिलाफ वहां के बोद्धों की प्रतिहिंसा के चलते उन्हें वहां से भागना पड़ा है, लेकिन क्योंकि वे मूल रूप से बांग्लादेशी हैं, इसलिए उन्हें वापस बांग्लादेश जाना चाहिए, न कि भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करनी चाहिए। भारत सरकार का तर्क है कि पडौसी मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिम वैध पासपोर्ट से भारत में आए, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद यहाँ से वापस नहीं गए, जबकि बाग्लादेश और म्यांमार से कोई भी मुस्लिम वैध तरीके से भारत में नहीं आया है।

पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार और मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अवैध घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा कर उन्हें चुनाव जीतने का औजार बना रखा है। इसी तरह असम और पूर्वोतर के अन्य सीमान्त राज्यों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने भी अवैध तरीके से उनके वोट बनवा दिए। अब इन दोनों राज्यों की भाजपा विरोधी पार्टियां चाहती हैं कि नागरिकता संशोधन क़ानून में इन घुसपैठियों को भी नागरिकता दी जाए। इन अवैध घुसपैठयों के खिलाफ अस्सी के दशक में बहुत बड़ा

आन्दोलन चला था, तबकी राजीव गांधी सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ किए समझौते में घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने का वायदा भी किया था, लेकिन वह वायदा किसी सरकार ने निभाया नहीं। क्योंकि अवैध घुसपैठिए उनका वोट बैंक बन गए थे।

इसलिए नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध करने वाले मुसलमानों के साथ विपक्षी पार्टियां भी शामिल थीं। मोदी सरकार ने देश भर में हुए हिंसक आन्दोलन के चलते क़ानून के नियम लागू नहीं किए थे। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह शुरू से कह रहे थे कि संसद से पारित क़ानून लागू किया ही जाएगा। अभी करीब एक महीना पहले से उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि लोकसभा चुनावों से पहले ही नागरिकता संशोधन क़ानून की नियमावली जारी कर दी जाएगी, और उसी के साथ ही क़ानून के दायरे में आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल और असम में तो यह एक बड़ा राजनीतिक विषय है, क्योंकि वहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशी हिन्दू रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें नागरिकता देकर अपने वोट बैंक में तब्दील करना चाहती है। जबकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस अपने बांग्लादेशी मुस्लिम वोट बैंक को भरमाते रहे हैं कि वे भेदभाव वाला यह क़ानून लागू नहीं होने देंगे, अगर केंद्र सरकार बांग्लादेशी हिन्दू शरणार्थियों को नागरिकता देगी, तो वे उन्हें भी नागरिकता दिलाएंगे।

विपक्षी दलों और मुस्लिमों के विरोध के चलते प्रतिक्रिया में यह क़ानून भारत के हिन्दुओं के लिए भी बड़ा मुद्दा बन गया था। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सार्वजनिक मंचों से मोदी सरकार को चुनौती देती रही थीं कि वह नागरिकता संशोधन क़ानून और नागरिकता रजिस्टर लागू करवा कर दिखाएं। इस चुनौती को अमित शाह सार्वजनिक मंचों से स्वीकार करते रहे हैं, लेकिन पिछले छह महीनों से संशय बना हुआ था कि सरकार चुनावों से ठीक पहले नागरिकता संशोधन क़ानून को लागू करके रिस्क लेना चाहेगी या नहीं। हालांकि भारत के नागरिकों का इस क़ानून से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा समर्थकों ने इस क़ानून को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। इसलिए लोकसभा चुनावों से पहले नियमावली लागू नहीं होती, तो इसे भाजपा सरकार की कमजोरी माना जाता।

चुनावों की घोषणा से करीब दस दिन पहले मोदी सरकार ने नियमावली लागू करके अपने काडर का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, दिल्ली और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बड़ा दांव खेल दिया हैं। इन सभी राज्यों में जहां बांग्लादेशी और म्यांमारी घुसपैठिए भरे पड़े हैं, वहीं पश्चिम बंगाल और असम में तो विपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण वोट बैंक है, तो इन्हीं दोनों देशों से आए हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन भाजपा का वोट बैंक हैं, जिन्हें भाजपा ने नागरिकता का तोहफा देकर अपने वोट को और मजबूत किया है। चुनावों में विपक्षी पार्टियों को अब यह वायदा करना पड़ सकता है कि सत्ता में आने पर वे नागरिकता संशोधन क़ानून में फिर संशोधन करेंगे और इस क़ानून को सेक्यूलर क़ानून बनाएंगे, जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान खत्म किया जाएगा। विपक्ष के इस वायदे से चुनावों में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण तेज होगा, जिसका विपक्ष को फायदा होने की बजाए नुकसान ही होगा, क्योंकि 2020 के नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ चले हिंसक आन्दोलन के घाव फिर हरे हो जाएंगे।

वैसे मोदी सरकार ने क़ानून की नियमावली लागू करके विपक्ष को एकजुट होने का सुअवसर प्रदान कर दिया है। मोदी सरकार चुनावों की घोषणा से पहले अपने बचे हुए काम निपटा देना चाहती है। चुनावों की घोषणा 19 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। 2019 में 10 मार्च को लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी, दस मार्च जा चुकी है और चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है। अब लोकसभा चुनावों की घोषणा 19-20 मार्च को संभावित है।

# बेहद कठिन परिस्थितियों में हुआ पहला आम चुनाव

**जयसिंह रावत**

चरम विज्ञान और प्राद्योगिकी के इस युग में व्यापक अधिकारों और संसाधनों से सुसज्जित तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराए जाने वाले चुनावों में कई कमियों के कारण निष्पक्ष तथा स्वतंत्र निर्वाचन के लिए अभी भी बहुत कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन कल्पना कीजिए कि संसाधनों के अकाल और अनुभव शून्यता के बावजूद एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग ने किस तरह 1951-52 में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के पहले आम चुनाव को सम्पन्न कराया होगा। यह सचमुच विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी।

देश के विशाल आकार, विविध जनसंख्या और जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव कराना वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। उस समय सड़कों के घोर अभाव के कारण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्थापित करना, चुनाव सामग्री पहुंचाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन कार्य था। उस अधिकांश भारतवासी अशिक्षित थे और मतदान की अवधारणा से अपरिचित थे। मतदान प्रक्रिया और लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को समझाने के लिए व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान आवश्यक थे।

नए-नए आजाद हुए भारत का 1951-52 में बुनियादी ढाँचा अविकसित था। सीमित परिवहन, संचार और प्रशासनिक सुविधाओं ने राष्ट्रव्यापी चुनाव कराने में महत्वपूर्ण चुनौतियां स्वाभाविक ही थीं। भारत की विविध आबादी में विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और संभावित संघर्षों के प्रबंधन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती थी। इन चुनौतियों के बावजूद, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में भारत के निर्वाचन आयोग ने सफलतापूर्वक चुनाव कराया। यह

उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था, जिसमें 17.3 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इस चुनाव को व्यापक रूप से भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को गठित भारत निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन की नियुक्ति 21 मार्च 1950 को हुई थी। उनके समक्ष दुनिया के सबसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बेहद कठिन चुनौतियां थी। इन चुनौतियों के बावजूद, आयोग ने 1951-52 में पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया। उस समय भी जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरे नम्बर का देश था। इसलिए जनसंख्या के हिसाब से भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था। कठिनतम चुनौतियों के बीच निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर 1951 को चार चरणों में लोकसभा और तीन तरह की विधानसभाओं के आम चुनाव घोषित किए। चुनाव का पहला चरण 25 अक्टूबर 1951, दूसरा 31 अक्टूबर, तीसरा 6 नवम्बर और चैथे चरण का मतदान 15 नवम्बर 1951 को सम्पन्न हुआ। चुनावों के नतीजे 21 फरवरी 1952 को घोषित किए गए। इस तरह सम्पूर्ण निर्वाचन प्रकृया मार्च 1952 में सम्पन्न हुई। इसमें लगभग 17.3 करोड़ मतदाताओं (44.99 प्रतिशत) ने भाग लिए। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस भारी अंतर से विजयी रही। उस समय कुल लोकसभा की 496 में से 489 पर चुनाव हुए जिनमें से नेहरू के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 384, अजय घोष के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 तथा जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिलीं थी। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने 21 मार्च 1951 को पहले चुनाव के बारे में ऑल इंडिया रेडियो से देश को पहला संबोधन किया था। इस संबोधन में उन्होंने भारतवासियों से निर्वाचन प्रकृया में निडर हो कर स्वतंत्र रूप से भागीदारी निभाने की अपील करने के साथ ही आयोग के समक्ष बेहद कठिन चुनौतियों को भी गिनाया था।

इन चुनौतियों में संशाधनों के अभाव के साथ ही पहले परिसीमन की जटिलता का भी उल्लेख किया था। क्योंकि उस समय लोकसभा के साथ ही तीन तरह की विधानसभाओं के चुनाव होने थे और लोकसभा में भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें अलग से आरक्षित न हो कर इन जातियों की जनसंख्या के आधार पर उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में दुहरे मतदान की व्यवस्था थी। संविधान में लोकसभा के लिए अधिकतम 500 सीटें और उस समय के लिए 496 सीटें तय थीं। संविधान के अनुसार जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान निकोबार के सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होना था और शेष भारत के लिए वयस्क मतदान से सांसदों को चुना जाना था। उस समय राज्यसभा की 204 सीटें तय थीं जो कि तीनों तरह के राज्यों से भरी जानीं थीं। राज्यसभा के लिए साहित्य विज्ञान, कला और समाजसेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मानोनीत होने थे। 204 सदस्यों में से 190 का चयन राज्यों से समानुपातिक प्रतिनिधित्व (जम्मू-कश्मीर के अलावा) और 10 सदस्यों का चयन पार्ट-सी के राज्यों से वयस्क मताधिकार से होना था। राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर से 4 सदस्यों का मनोनयन होना था।

पहले आम चुनाव के समय देश में तीन तरह के 28 राज्य थे। इनमें पार्ट-ए के 9 राज्यों में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश ( पूर्ववर्ती सेंट्रल प्रोविन्सेज), उत्तर प्रदेश (पूर्ववर्ती संयुक्त प्रान्त), पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा और पंजाब शामिल थे।

# बदायूं नहीं, संभल से चुनाव लड़ना चाहते हैं शिवपाल, अखिलेश की मुश्किल बढ़ी

**अजय कुमार**

समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट को लेकर गफलत में नजर आ रही है। चर्चा है कि एक बार फिर सपा आलाकमान ने वहां से शिवपाल यादव की उम्मीदवारी खारिज कर दी है। शिवपाल स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे या फिर यह पार्टी आलाकमान का फैसला है इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बदायूं में सपा की सियासी करवट पर सपा के दिग्गजों में हर स्तर पर दो तरह की राय सामने आई हैं। एक बड़ा वर्ग बदायूं से सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को फिर से उम्मीदवार बनाना चाहता है, जबकि सपा के ही कुछ नेता धर्मेंद्र यादव से नाराज बताये जाते हैं। वह उनको न लड़ाए जाने का आग्रह पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी कर चुके हैं। इसके बाद ही धर्मेंद्र यादव के स्थान पर शिवपाल सिंह यादव का नाम आया था। अब सपा के सूत्रों का कहना है कि खुद शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि शिवपाल की पहली पसंद संभल बताई जा रही है। सपा ने संभल से शफीकुर्रहमान बर्क को टिकट दिया था, लेकिन उनका देहांत हो चुका है, जिसकी वजह से यहां नये उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। इसलिए पहले उनका बदायूं आगमन टला, फिर लगातार दूसरी बार उनके बेटे आदित्य यादव का भी दौरा टल गया। आदित्य यादव को अपने पिता शिवपाल यादव की चुनावी कमान संभालने के लिए यहां आना था। उनका दो बार दौरा लगा पर एक बार भी नहीं आए। संभल एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां से सपा कई चुनाव जीत चुकी है। सपाइयों ने बताया था कि आदित्य यादव का आज यानी 11 मार्च को बदायूं में आने का कार्यक्रम था, सपाइयों ने उनके स्वागत और चुनावी अभियान की शुरुआत को लेकर तैयारी बैठक कर ली, लेकिन एक दिन पहले 10 मार्च को उनका कार्यक्रम निरस्त होने की जानकारी सामने आई। इसकी पुष्टि सपा के स्थानीय पदाधिकारियों ने भी की। बताया गया कि आदित्य यादव का कार्यक्रम टल गया है। इससे अब उम्मीदवार बदले जाने की संभावना जताई जाने लगी है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि अब तक कोई चुनावी बैठक भी नहीं हुई है। फिलहाल, स्थानीय पदाधिकारियों की निगाहें नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं। गौरतलब है कि बदायूं मुस्लिम और यादव बहुल सीट है। इसी समीकरण से किसी समय यह सपा की मजबूत सीट मानी जाती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई और सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को शिकस्त देने के लिए संघमित्रा मौर्य को मैदान में उतारा था। भाजपा प्रत्याशी से धर्मेंद्र यादव हार गए थे। चुनाव के बाद सियासी घटनाक्रम बदलता रहा। संघ मित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहे। सपा में रहते केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर सियासी हमले किए। तब से भाजपा के अंदर उनकी बेटी के टिकट लेकर संशय हो गया है। पहली लिस्ट में नाम न आने पर संशय और बढ़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से नाता तोड़ने के बाद सपा आलाकमान बदायूं सीट को लेकर काफी गंभीर हो गया है। इस सीट को सपा ने अपने पाले में करने के लिए शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा है। यह अलग बात है कि शिवपाल सिंह के आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी और सपा केराष्ट्रीय सचिव रहे आबिद रजा की चुनौती सामने आई है। दोनों ने सेक्युलर फ्रंट बनाकर सहसवान में बड़ी रैली की। इसके बाद सपा के लिए बड़ी चुनौती सामने आ रही है। पार्टी बदायूं में जिस तरह से अंतरकलह से जूझ रही है, उससे लगता है कि सपा के लिये यहां चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

# हथेलियों की ये छोटी-छोटी रेखाएं, देती हैं खास संकेत

हथेलियों की बड़ी रेखाएं जैसे हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन और भाग्य रेखा हर किसी का ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन हथेलियों की छोटी-छोटी और बारीक रेखाएं भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। यह रेखाएं व्यक्ति के चरित्र, योग्यताओं और भविष्य की घटनाओं के बारे संकेत देती हैं।

## हथेलियों की छोटी रेखाएं

व्यक्ति की हथेलियों पर कई छोटी रेखाएं मौजूद होती हैं। इन रेखाओं का महत्व उनकी स्थिति, लंबाई, गहराई और एक रेखा का दूसरी रेखाओं को काटने पर निर्भर करता है। चलिए हम इन छोटी-छोटी रेखाओं के अर्थ के बारे में जानते हैं।

**मर्करी लाइन:** इसे हेल्थ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह हेड लाइन के समांतर होती है और व्यक्ति के कल्याण, मनोदशा और ओवर ऑल हेल्थ से जुड़ी होती है। एक साफ और सीधी मर्करी लाइन व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाती है, जबकि टूटी हुई मर्करी लाइन जातक के लंबी बीमारी या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को व्यक्त करती है।

**अपोलो लाइन:** अपोलो लाइन को सन लाइन भी कहते हैं। यह रिंग फिंगर और हार्ट लाइन के बीच वर्टिकल लाइन में होती है। यह कला,लीडरशिप और सफलता के क्षेत्र में क्रिएटिविटी, सक्सेस, और पहचान को प्रस्तुत करती है। एक आसानी से देखी जाने वाली और सीधी अपोलो लाइन टैलेंट, महत्वकांक्षा और फेम को व्यक्त करती है।

**शुक्र वलय:** यह रेखा अंगूठे के बगल की उंगली और छोटी उंगली के बीच क्षैतिज रेखा में एक वृत्तीय चाप बनाती है। यह रेखा व्यक्ति के स्वभाव, संवेदनशीलता और अंतरात्मा से जुड़ी होती है। एक गहरी शुक्र वलय रेखा व्यक्ति के जटिल और जुनूनी स्वभाव का संकेत देती है।

**ट्रैवल लाइन:** यह रेखा हथेलियों पर कलाईयों के पास पाई जाती हैं। यह रेखा व्यक्ति की यात्रा और ट्रैवल का अनुभव बताती है। एक साफ-सुथरी ट्रैवल लाइन व्यक्ति की निरंतर यात्रा का संकेत देती है।

**मैरिज लाइन:** मैरिज लाइन छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे किनारे की ओर स्थित होती है। यह व्यक्ति के रिलेशनशिप, शादी और प्यार के बारे में संकेत देती हैं। इस रेखा से व्यक्ति के रिलेशनशिप, शादी का अनुभव और शादी का समय तक बताया जा सकता है।

# घर में करेले का पौधा लगाना शुभ है या अशुभ, जानें क्या कहता है वास्तु

घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ पेड़ों को सजाया जाता है। कुछ लोग टमाटर, कद्दू आदि सब्जियों के बगीचे लगाते हैं। आप घर पर केवल ऐसे बगीचे नहीं उगा सकते। ज्योतिष शास्त्र में पेड़-पौधों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा विधिवत रूप से करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती है और ग्रहदोष से भी छुटकारा मिल सकता है। घर में कई तरह के पेड़-पौधे लगाते हैं, जो शुभ और अशुभ माने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ -पौधे होते हैं जो घर में गलती से लगने से अशुभ परिणाम देते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या घर में करेले का पौधा लगा सकते हैं या नहीं? आइए जानते हैं विस्तार से।

## वास्तु के अनुसार घर में न लगाएं करेले का पौधा

वास्तु शास्त्र में कई पेड़-पौधे घर में लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन एक पौधा ऐसा है जिसे गलती से भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार रेले का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे को लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और व्यक्ति को अशुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। मान्यता है कि करेला कड़वी सब्जी मानी जाती है और इससे निकलने वाली ऊर्जा भी नकारात्मक होती है। करेले का पौधा घर के बाहर लगाया जा सकता है। मगर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर की दक्षिण दिशा की तरफ यह पौधा नहीं लगा होना चाहिए। अगर करेले का पौधा दक्षिण दिशा में लगा है तो घर में हमेशा कलह-क्लेश होता है।

## आर्थिक स्थिति हो सकती है कमजोर

वास्तु के अनुसार घर में करेले का पौधा लगाने से इसका प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। व्यक्ति को कर्ज संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि करेले के पौधे को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं इससे व्यक्ति का मान-सम्मान प्रभावित हो सकता है।

## मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार अगर आप घर में करेले का पौधा लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी धन का आगमन नहीं होता है और खर्च बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी करेले का पौधा न लगाएं।

# पश्चिम दिशा में बेडरूम होने पर पति-पत्नी में होता है विवाद

## वास्तु नियमों को न करें अनदेखा

वास्तु शास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कई तरह के उपायों के बारे में बताया गया है। वहीं अगर पश्चिम दिशा में कोई दोष होता है तो गृहस्वामी और घर के सदस्यों को कई तरह की परेशानियां होती हैं।

वास्तु शास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कई तरह के उपायों के बारे में बताया गया है। घर की पश्चिम दिशा को काफी अहम माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पश्चिम दिशा में कोई भी दोष होने का अर्थ है कि खुद को परेशानी और परिवार को परेशानी होना।

बता दें कि पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण, आयुध पाश और प्रतिनिधि ग्रह शनिदेव होते हैं। पश्चिम दिशा से कालपुरुष के पेट, गुप्तांग और जननांग का विचार किया जाता है। यदि इस दिशा

में दोष होता है तो घर के स्वामी की आमदनी अच्छी नहीं रहती है और उसे यौन संबंधी बीमारी होने का अंदेशा रहता है।

## पश्चिम दिशा के वास्तु उपाय

घर की पश्चिम दिशा को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। इसके साथ ही यदि घर की पश्चिम दिशा की दीवार में दरारें हैं, तो इससे आपको और आपके परिवार को शनि का कुप्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। वहीं घर के स्वामी की आमदनी भी प्रभावित होती है।

इसके साथ ही अगर यदि पति-पत्नी का बेडरूम पश्चिम दिशा में है तो उनमें पटरी ठीक से नहीं बैठती है। दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होते रहते हैं और लंबे समय तक साथ नहीं रह पाते हैं। यानी की पति-पत्नी में डायवोर्स भी हो सकता है। वहीं अगर विवाद न हो तो अन्य कई कारणों से पति-पत्नी को अलग-अलग रहना पड़ सकता है।

घर के पश्चिम दिशा में पूजा घर होने से गृहस्वामी ज्योतिष और तंत्र-मंत्र आदि विधाओं का जानकार होता है। वहीं अगर इस दिशा में रसोई बनी है तो धन का आगमन तो होता है, लेकिन वह धन टिकता नहीं है।

पश्चिम दिशा में अग्निस्थल होने पर घर के सदस्यों को बार-बार गर्मी, पित्त, एसिडिटी जैसी समस्याएं होती रहती हैं। वहीं पश्चिम दिशा में लगा दरवाजा छोटा होने पर गृहस्वामी की उन्नति में बाधा आती रहती है।

पश्चिम दिशा में बना गेट अगर नैऋत्यमुखी हो, तो परिवार के सदस्यों को कोई लंबी बीमारी और असाध्य रोग होने का खतरा होता है। वहीं ऐसे द्वारा के होने पर असामयिक मृत्यु भी हो सकती है।

पश्चिम दिशा में बना गेट वायव्यमुखी होने पर मकान मालिक कोर्ट-कचहरी के मामलों में फंसा रहता है। जिसके कारण उसका काफी धन व्यय होता रहता है।

# नारियल का छोटा सा उपाय आर्थिक तंगी से दिलाएगा मुक्ति, दुर्भाग्य हो जाएगा दूर

हिंदू धर्म में वास्तु दोष के बारे में कई बातें बताई गई है। माना जाता है कि वास्तु दोष लगने से व्यक्ति के अच्छे-खासे जीवन में उतार-चढ़ाव आने लगते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में सफलता नहीं पाता और जीवन में कोई न कोई मुसीबत लगी रहती है। वास्तु दोष के कारण आमदनी कम और खर्च अधिक होने लगता है।

वहीं परिवार के सदस्यों के बीच अनबन होने लगती है। अगर आप भी वास्तु दोष के कारण अपने जीवन से परेशान हो गए हैं। तो नारियल के इस्तेमाल से आप वास्तु दोष से निजात पा सकते हैं। नारियल का उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करता है।

## वास्तु दोष से बचने के उपाय

बता दें कि सनातन धर्म में नारियल को काफी शुभ माना जाता है। हर शुभ काम से पहले नारियल फोड़कर श्रीगणेश किया जाता है। वहीं कलश पूजा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि नारियल मां लक्ष्मी को अतिप्रिय है। इसलिए आप शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के सामने नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो गए हैं और इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। तो शुक्रवार के दिन जटा वाला नारियल ले लें। अब मां लक्ष्मी को मंदिर जाकर उन्हें जटा वाला नारियल, सफेद मिठाई, दही, एक कमल का फूल और सफेद वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर घर में ऐसे स्थान पर रखें। जहां पर किसी अन्य व्यक्ति की नजर ना पड़े। इस उपाय को करने से जल्द ही आपको आर्थिक समस्या से निजात मिलेगा।

अगर आपका काम भी बनते-बनते बिगड़ जाता है। तो एक नारियल आपके तरक्की के मार्ग खोल सकता है। सबसे पहले एक नारियल पर काजल से टीका लगाएं। फिर इसे घुमाकर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से बुरी नजर और बुरी बला टल जाती है।

आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति को मंगलवार के दिन यह उपाय करना चाहिए। सबसे पहले एक जटा वाला नारियल ले लें। अब इसमें चमेली का तेल लगा दें। वहीं नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इस नारियल को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में अर्पित कर दें। इस उपाय को 7 मंगलवार करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

# मकान के वास्तु दोष से हैं परेशान? बिना तोड़फोड़ के ऐसे दूर होगा अशुभ प्रभाव

कई लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इसके अलावा हमेशा गृह कलह और घर में तू तो मैं मैं की स्थिति रहती है। इसका बहुत बड़ा कारण आपके घर का वास्तु भी है। अगर आपके घर का वास्तु सही नहीं है तो जीवन में आपको कई तरह की समस्याओं जैसे खराब स्वास्थ्य, करियर में परेशानियां, धन की हानि और व्यापार में असफलता जैसी परेशानियां लगी रहती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनको आप घर में बिना तोड़फोड़ किए हुए अपना सकते हैं।

## घर के ईशान कोण में रखें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का उत्तर पूर्वी कोना जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, को एक्टिव करना चाहिए। इस दिशा में आप उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर, नदियों या उगते सूरज की तस्वीर को लगा सकते हैं। ऐसा करना घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है और निगेटिव एनर्जी को कम करता है।

## किचन से वास्तु दोष हटाने के लिए करें ये उपाय

अगर आपकी रसोई वास्तु के अनुसार गलत जगह पर है तो आप अग्नि कोण में लाल बल्ब लगा सकते हैं। इसे हर रोज सुबह शाम जलाएं। ऐसा करने से रसोई का वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है।

## घर की पश्चिम दिशा में करें ये काम

अगर आपके घर के पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष है तो इसके लिए आप इस दिशा में शनि यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं।

## इस दिशा में लगाएं गणेश जी की मूर्ति

अगर घर के अग्नि कोण में वास्तु दोष है तो इस दिशा में आप गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिशा में मनी प्लांट का पौधा भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन-समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। परिवार के बीच प्रेम भाव बना रहेगा। नौकरी-व्यवसाय में भी जल्दी सफलता मिलेगी।

# घर की नेगेटिव एनर्जी को इन आसान उपायों से करें दूर, सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि

जब भी नकारात्मक ऊर्जा की बात होती है, तो हमारे घर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं। जहां पर यह नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। इसके लिए आप वास्तु के कुछ आसान उपाय भी अपना सकते हैं।

जब भी नकारात्मक ऊर्जा की बात होती है, तो हमारे घर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं। जहां पर यह नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि जब हम अपने स्थान पर होते हैं, तो हमारे आसपास मौजूद कुछ शक्तियां इस ऊर्जा को ज्यादा बढ़ावा देती हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि लगातार हम इसके संपर्क में रहते हैं। हांलाकि कारण जो भी हो, लेकिन हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन पर बुरा असर डाल सकती है।

अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका घर पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो। विभिन्न स्त्रोतों से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। वहीं इस नकारात्मक ऊर्जा को फौरन दूर करना जरूरी होता है। ताकि आपके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के कुछ आसान वास्तु उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं।

## खुली रखें घर की खिड़कियां

आपको सुबह सोकर उठने के साथ ही घर की खिड़कियां खोल देनी चाहिए। जिससे कि आपके घर में सूरज की रोशनी आ सके और ताजी हवा अंदर आ सके। किसी भी स्थिर ऊर्जा को यह उपाय साफ करने में मदद करेगा। इसके अलावा घर को व्यवस्थित करने के लिए भी थोड़ा समय निकाले। कभी भी घर

को अस्त-व्यस्त नहीं छोड़ना चाहिए। यह उपाय आपके घर की ऊर्जा प्रवाह को बेहतर बनाने में मददगार होगा।

## पुरानी और खराब चीजें हटा दें

घर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए कभी भी घर में बेकार, पुरानी और खराब चीजों को नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीजों को घर से फौरन हटा देना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर घड़ी खराब हो गयी है, तो उसे हटा दें। वहीं घर में कोई भी टूटा सामान और बर्तन नहीं रखने चाहिए।

## मोमबत्तियां, क्रिस्टल और पौधे

आपको बता दें कि घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप मोमबत्तियों, क्रिस्टल और पौधों को घर में जगह दे सकते हैं। घर के माहौल को अधिक से अधिक शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करें। इन सारी चीजों को घर पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही यह उपाय नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में मदद करता है।

## फेंग शुई का उपयोग

अगर आप किराए के घर या अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए फेंग शुई का उपयोग करें। यह प्राचीन चीनी प्रथा %ची% नामक ऊर्जा के प्रवाह पर आधारित है। अगर आपको नहीं पता कि यह कैसे करना है, तो आप किसी आप प्रोफेशनल फेंगशुई या वास्तु एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं।

## स्मज स्टिक

आप अपने घर में रोजाना स्मज स्टिक का उपयोग करें। इसके लिए आप लोबान, मगवोर्ट, सेज, लैवेंडर, पालो सैंटो और ड्रेगन ब्लड की स्मज स्टिक का उपयोग कर सकते हैं। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। घर में स्मज स्टिक जलाकर उसका धुंआ करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

## मंत्रों का उच्चारण

सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्टदेव का ध्यान कर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप मंत्रोच्चारण करना नहीं चाहते हैं, तो स्पीकर पर मंत्र और गाने चला सकते हैं। मंत्रों में आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी का सबसे अच्छा मंत्र गायत्री मंत्र हो सकता है। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस जाप से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

## अरुणाचल देश का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा

**नईदिल्ली।** भारत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक सख्त बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा पर चीन द्वारा आपत्ति जताना तर्कसंगत नहीं है। सरकार ने यह भी दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बयान में कहा गया कि हम प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के संबंध में चीनी पक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज करते हैं। भारतीय नेता समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, जैसे वे भारत के अन्य राज्यों का दौरा करते हैं। ऐसी यात्राओं या भारत की विकासात्मक परियोजनाओं पर आपत्ति करना उचित नहीं है। इसके अलावा, यह इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।

## हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया

**चंडीगढ़।** हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में भाजपा और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के बीच विभाजन की अटकलों के बीच मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह घटनाक्रम आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सामने आया है। खट्टर ने राजभवन जाकर बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हरियाणा सरकार में बीजेपी और जेजेपी के बीच चल रही तनातनी के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी और सरकार समर्थित निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई। सीएम ने मंगलवार सुबह 11:30 बजे बीजेपी और सरकार समर्थित निर्दलीय विधायकों को हरियाणा आवास पर बुलाया। इस बैठक में बीजेपी निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने के फॉर्मूले को लेकर रणनीति की खबर है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 41 विधायक, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। सात निर्दलीय हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल और एचएलपी का एक-एक विधायक है।

## लालू यादव के करीबी अमित कात्याल पर ईडी का छापा

**पटना।** लालू यादव के करीबी और कारोबारी अमित कात्याल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) छापेमारी कर रही है। दिल्ली, गुरुगुग्राम और सोनीपत में कात्याल के कई ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अमित कात्याल के यहां छापा मारा है। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत में कार्रवाई की है। अमित कात्याल पर पहले भी जांच एजेंसी एक्शन ले चुकी है। लैंड फॉर जॉब केस में अमित कात्याल को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। अमित कात्याल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दोस्त बताए जाते हैं। वह एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर हैं। मार्च 2023 में ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी और उनकी बहनों एवं अन्य आरोपियों के ठिकानों पर रेड की थी।

## सीएए लागू होने पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा

**कोलकाता।** केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भाजपा समर्थक जहां सरकार के इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले सीएए लागू करने को बंटवारे की राजनीति करार दिया। वहीं, अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर संदेह जताया है कि यह कानून वैध भी या नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनकी संपत्ति का क्या होगा? इससे आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। यह अधिकार छीनने का खेला है। आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा। केंद्र सरकार सुन ले मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी।

## गठबंधन को लेकर प्रकाश आंबेडकर की खरगे को चिट्ठी

**मुंबई।** लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के सीट बंटवारें को लेकर बहुजन वंचित अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिकर्जुन खरगे को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की पांच सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा-शरदचंद्र पवार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। अपनी चिट्ठी में प्रकाश अंबेडकर ने कहा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हो ही जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए अपने बीच सीट शेयरिंग समीकरण को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। आलस और जल्दबाजी के बावजूद हम सकारात्मक है। कम से कम इतना कहा जा सकता है कि एमवीए का यह रवैया चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा, मैं समझ सकता हूं कि महाराष्ट्र की पांच सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा-शरदचंद्र पवार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। यही असली वजह है कि एमवीए सीट शेयरिंग समीकरण पर इतना समय ले रही है।

### सीएए के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मोर्चा संभाला, कहा-

# इज्जत और अधिकार देता है नागरिकता संशोधन कानून

**नई दिल्ली।** मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लगाए जाने का स्वागत किया है। मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहिद सईद ने कहा कि दुनिया के अनेकों देशों में सीएए कानून बहुत पहले से लागू है और यह देश की तरक्की, अमन और हिफाजत के लिए जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि रमजान के पाक व मोकद्दस महीने में सरकार ने साधुवाद भरा कदम उठाया है। यह कानून नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार की अध्यक्षता में 6 जून से 10 जून तक भोपाल में हुए चार दिवसीय कार्यशाला में मंच ने 11 मुद्दों पर ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया था, जिनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी- यूनिफॉर्म सिविल कोड) और नागरिक संशोधन कानून (सीएए-सिटिजनशिप अमेंडमेंड एक्ट) भी शामिल था।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल ने बताया कि भोपाल कार्यशाला जिसमें मंच के एक हजार से अधिक बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता तथा विभिन्न अधिकारियों ने शिरकत की थी उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि देश के हर मुसलमान को इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएए लागू होने से मुसलमान कतई नहीं घबराएं, यह कानून इज्जत और अधिकार देता है। लोगों को नागरिकता देता है न की छीनता है। और इससे मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए अगर इस्लाम और मुसलमानों के तथाकथित रहनुमा और मजहबी ठेकेदार अगर नफरत, हिंसा और भड़काने का काम करते हैं तो ऐसे देश के गुनहगारों को मुसलमान तवज्जो न दे। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रहित व सुरक्षा से समझौता कर राजनीति करते रहे हैं। भोली- भाली जानता को भड़काने की कोशिश कर मुल्क का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जाता रहा है। जो देश के विकास के लिए घातक और चिंताजनक है।

देश के अनेकों संवेदनशील मामलों में मंच का क्या रुख है और संविधान और इस्लाम के दायरे में रहते हुए भारतीय मुसलमानों का क्या रोल को यह सब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पुस्तक भारतीय मुसलमान = एकता का आधार हुब्बुल वतनी (राष्ट्रीयता) में विस्तार से बताया गया है। यह सभी कुछ भारतीय मुस्लिम विद्वानों द्वारा मुस्लिम समाज के मार्गदर्शन के लिए किया गया है। इस किताब को रिफ्रेंस एंड रिसर्च गाइड के रूप में जाना जाएगा। किताब के संपादक और मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद अख्तर ने बताया कि भारतीय मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं वो सब इस किताब के जरिए समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह किताब एक ऐसे ग्रंथ की तरह है जो भारतीय मुसलमान को जीने का सही रास्ता बताती है। संविधान, दीन और इस्लाम की दिखाई रोशनी में भारतीय मुसलमानों की कैसी सोच होनी चाहिए, साथ ही देशवासियों की कैसी सोच होनी चाहिए इस पुस्तक की विशेषता है। किताब यह संदेश देती है कि देश के संदर्भ में राष्ट्रीयता और विश्व के संदर्भ में मानवता सर्वोपरि है।

यह किताब विदेशी आक्रांताओं और भारतीय मुसलमान के बीच का फर्क समझाती है। किताब बताती है कि राष्ट्रीयता और मानवता मजहब से ऊपर होती है। क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बेसिक सोच नेशन फर्स्ट को लेकर चलती है। मंच का मकसद होता है एकता, अखंडता, संप्रभुता, समरसता। मंच का मानना है तालीम जिंदगी के लिए और जिंदगी वतन के लिए है। मंच का उद्देश्य होता है कि भले ही हम आधी रोटी खाएं लेकिन बच्चों को तालीम और तरबियत जरूर दें। किताब में संविधान और इस्लाम की रोशनी में निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से नजरिया पेश किया गया है-

1. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सर्वधर्म समभाव पर ज़ोर।
2. भारतीय मुसलमान और समान नागरिक संहिता।
3. शरीयत और एक देश एक कानून।
4. भारतीय मुसलमान : परंपराएं, संस्कृति और पहचान।
5. भारतीय मुसलमान, कल आज और कल।
6. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय मुसलमान।
7. राष्ट्रीय परिवेश में भारतीय मुसलमान।
8. भारत में मुस्लिम जनसंख्या और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण।
9. कुरान इस्लाम और संस्कृति।
10. इस्लाम और कुरान में रैहान (तुलसी)।
11. मज़हब से परे योग।
12. गाय और इस्लाम।
13. अमृत काल और मुस्लिम युवा।
14. आज का मुस्लिम : चुनौतियां और समाधान।
15. अमृतकाल में युवाओं की भूमिका।
16. कुरान की रोशनी में मुस्लिम ख्वातीन।
17. भारतीय मुसलमान अमृतलाल से पहले और बाद में।
18. भारतीय मुसलमान : स्वतंत्रता आंदोलन से अमृत काल तक।
19. जम्मू कश्मीर : धारा 370 के पहले और बाद।
20. राष्ट्रवाद की राह पर भारतीय मुसलमान : 2014 से अब तक।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि यह किताब नफरतें, बंटवारा और हिंसा से मुक्ति का मार्ग है। भाईचारे, तालीम, तरक्की का मार्ग है। पुस्तक उस जहर की भी काट है जो वोटबैंक के खातिर राजनीति दलों, कट्टर मजहबी एवं तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के जरिए फैलाए जाते हैं। साथ ही यह किताब वैसे लोगों का पर्दाफाश भी करती है जो मुसलमान को भारतीयता और राष्ट्रीयता से दूर करने की साजिशें रचते रहते हैं। यह किताब समाज में बोए जाने वाली नफरतों से बाहर निकल कर सच्चाई और अमन के रास्ते पर चलने का रास्ता बताती है। भारतीय मुसलमान = एकता का आधार हब्बुल वतनी (राष्ट्रीयता) नफरतों से मुक्ति का रास्ता देती है। यह किताब हमें अपने जड़ों से जोड़ती है।

### गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी ने दी 85,000 करोड़ की सौगात, कहा-

# हम राष्ट्र निर्माण के लिए विकास कार्य करते हैं, न कि चुनाव जीतने के लिए

**अहमदाबाद।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र निर्माण के अपने मिशन के तहत विकास कार्य करती है, न कि चुनाव जीतने के लिए ऐसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 10 नयी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने के साथ 85,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर कहा, ''कुछ लोग हमारे प्रयासों को चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम राष्ट्र निर्माण के मिशन के तहत विकास कार्य करते हैं, न कि (चुनाव जीतकर) सरकार बनाने के लिए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे युवाओं को वह कष्ट न सहना पड़े जो उनकी पिछली पीढ़ियों को झेलना पड़ा। यह मोदी की गारंटी है।''

उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्ष में उनकी सरकार ने रेलवे के विकास पर पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक राशि खर्च की है। मोदी ने कहा, ''वर्ष 2024 के केवल दो महीनों में, हमने 11 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।'' उन्होंने कहा, ''मैंने अपना जीवन रेलवे पटरियों पर शुरू किया, इसलिए मुझे पता है कि पहले हमारी रेलवे की स्थिति कितनी खराब थी।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अलग रेलवे बजट की व्यवस्था को समाप्त कर इसे केंद्रीय बजट में शामिल किया ताकि सरकारी पैसे का इस्तेमाल रेलवे के विकास में किया जा सके। उन्होंने कहा विकसित भारत के लिए सुधार किए जा रहे हैं और देश के हर हिस्से में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि रेलवे कितनी खराब थी क्योंकि उन्होंने अपना जीवन रेलवे ट्रैक पर शुरू किया है। पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे का विकास विकसित भारत की गारंटी है. उन्होंने कहा, हम दुनिया में कहीं भी नजर डालें तो पाएंगे कि जो देश विकसित और आर्थिक



महाशक्ति बने, उनमें रेलवे ने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए, रेलवे का विकास विकसित भारत की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह दिन इच्छाशक्ति का जीता-जागता सबूत है। देश के युवा तय करेंगे कि उन्हें कैसा देश और रेलवे चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। 10 साल का काम अभी भी एक ट्रेलर है, मुझे अभी और हासिल करना है।) रेलवे के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, प्रधान मंत्री ने 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे और पेट्रोकेमिकल्स परियोजनाओं की आधारशिला रखने और समर्पित करने के लिए अहमदाबाद में डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा किया।

प्रधानमंत्री ने चार वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद-जामनगर वंदे भारत को द्वारका तक बढ़ाया जा रहा है, अजमेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत को चंडीगढ़ तक बढ़ाया जा रहा है, गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज तक बढ़ाया जा रहा है और तिरुवनंतपुरम-कासरगोड वंदे भारत को मंगलुरु तक बढ़ाया जा रहा है, और आसनसोल और हटिया तथा तिरूपति और कोल्लम स्टेशनों के बीच दो नई यात्री ट्रेनें। उन्होंने विभिन्न स्थानों - न्यू खुर्जा जंक्शन, साहनेवाल, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड और न्यू मकरपुरा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाई।

खेल
प्रमुख समाचार

## आईपीएल में हो रही है ऋषभ पंत की वापसी

**नईदिल्ली।** पंत आईपीएल के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में फिट घोषित, शमी और प्रसिद्ध टूर्नामेंट से बाहर नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को ऋषभ पंत को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया।

पंत को एक साल से भी अधिक समय पहले एक दर्दनाक कार दुर्घटना में काफी चोटें लगी थी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले पंत विस्तृत रिहैबिलिटेशन से गुजरने के बाद 22 मार्च से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में दोहरी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। पिछले साल विश्व कप फाइनल के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर गुजरात टाइटंस के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले प्रसिद्ध कृष्णा चोटों के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ''30 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के रूड़की में पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में चोटिल होने के बाद 14 महीने के विस्तृत रिहैबिलिटेशन और उबरने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ऋषभ पंत को आगामी आईपीएल 2024 के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में फिट घोषित किया गया है।'' पंत पिछले साल आईपीएल नीलामी के दौरान कैपिटल्स के अधिकारियों के साथ मौजूद थे और दुर्घटना के बाद से वह एनसीए में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। दुर्घटना में पंत के दाहिने घुटने में गंभीर चोट लग गई थी जिसके कारण कलाई और टखने में फ्रैक्चर के अलावा उन्हें लिगामेंट की सर्जरी करानी पड़ी। शमी एड़ी की सर्जरी से उबर रहे हैं और इस साल सितंबर से पहले उनकी वापसी की उम्मीद नहीं है। बीसीसीआई ने कहा, ''इस तेज गेंदबाज की दाहिनी एड़ी की समस्या के लिए 26 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक सर्जरी हुई।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

## सेंसेक्स 165 अंक चढ़कर 73,342 पर बंद, निफ्टी स्थिर

**नईदिल्ली।** हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार (12 मार्च) को फ्रंटलाइन इक्विटी सूचकांकों ने व्यापक बाजार में रुझान को उलट दिया और सेंसेक्स में भारी हिस्सदारी रखने वाले एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज में बढ़त के दम पर देसी शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 165 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी महज 3 अंक की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 165.32 अंक यानी 0.22 फीसदी की बढ़त के साथ 73,667.96 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 73,342.12 और 74,004.16 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 3.05 अंक यानी 0.01 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 22,335.70 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 22,256.00 और 22,452.55 के रेंज में कारोबार हुआ।

## भारत की बढ़ी धाक! अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण

**नईदिल्ली।** भारत ने 11 मार्च को स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि-5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र का परीक्षण किया। मिसाइल अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र के सफल क्रियान्वयन के लिए डीआरडीओ वैज्ञानिक की सराहना की। एमआईआरवी तकनीक के साथ अग्नि-5 मिसाइल की सफल परीक्षण उड़ान देश की रक्षा को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास एमआईआरवी क्षमता है। यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर पैकेज से सुसज्जित है। सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया कि पुन: प्रवेश करने वाले वाहन वांछित सटीकता के भीतर लक्ष्य बिंदुओं तक पहुंचें

## अगले हफ्ते शुरू हो सकता है जेएसडब्ल्यू ग्रुप और एमजी मोटर इंडिया का ज्वाइंट वेंचर

**नईदिल्ली।** अगले हफ्ते की 20 तारीख को भारत के जेएसडब्ल्यू ग्रुप और एमजी मोटर इंडिया के ज्वाइंट वेंचर की शुरूआत हो सकती है। रिपोर्ट की मानें तो दोनों कंपनियों के इस वेंचर में करीब 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। दोनों कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए साथ आए हैं और एक ज्वाइंट वेंचर पर सहमति बनी है। बता दें, जेएसडब्ल्यू ग्रुप भारत की मल्टीनेशनल ग्रुप है जबकि एमजी मोटर इंडिया चाइनीज ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसएआईसी मोटर के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ एक ज्वाइंट वेंचर के रुप में काम करेंगी। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी इनवेस्टर एवरस्टोन कैपिटल ने भी एमजी मोटर के इंडिया ऑपरेशन में भी हिस्सेदारी हासिल कर ली है।

## पॉपुलर व्हीकल्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला

**नईदिल्ली।** पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। निवेशक इसमें 14 मार्च (गुरुवार) तक बोली लगा सकेंगे। अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़ी जरूरी बातें एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें- पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 280 से 295 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी आईपीओ के जरिए 601.55 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। इस राशि में से 250 करोड़ रुपये नए इश्यू के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि शेष 351.55 करोड़ रुपये ह्स्नस के लिए रखे गए हैं। बुक बिल्ड इश्यू बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग के लिए प्रस्तावित है। 19 मार्च को आईपीओ की लिस्टिंग होने की उम्मीद है। मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी के शेयर आज ग्रे मार्केट में रू. 26 के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

# संपत्ति बाजार : रियल एस्टेट एजेंट की जवाबदेही तय हो

**सतीश सिंह**

इंसान हो या पक्षी या फिर जानवर, सभी शाम को लौटकर अपने घर आते हैं, लेकिन भारत में आज भी बहुत कम लोग अपने घर के सपने को पूरा कर पाते हैं। अधिकांश लोगों का जीवन किराये के मकान में गुजर जाता है या फिर बिना किसी छत के। भारत में घरों के स्वामित्व का राष्ट्रीय औसत 86.6 फीसदी है। राज्यों में, सिक्किम में घर का स्वामित्व सबसे कम 64.5 फीसदी है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश, दमन और दीव में घर का स्वामित्व सबसे कम 38.3 फीसदी है।

नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार, देश की 58 फीसदी आबादी आज भी खेती-किसानी पर निर्भर है, लेकिन उनका ठीक से गुजर-बसर नहीं हो पा रहा है। इसलिए वे बेहतर रोजगार हासिल करने के लिए गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। इस वजह से शहरों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। चूंकि जमीन सीमित है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए खुद का मकान बनाना मुमकिन नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु शहरों और कस्बाई इलाकों में अपार्टमेंट संस्कृति का आगाज हुआ है।

आरंभ में छोटी पूंजी वाले डेवलपर एक साथ कई परियोजनाओं को शुरू कर देते थे, ताकि ज्यादा संख्या में खरीदारों से दो से तीन किस्तों की वसूली की जा सके। एक से अधिक परियोजनाओं को जीवित रखने के लिए वे फंड डाइवर्ट करते थे, अर्थात कभी 'एक्स' परियोजना का पैसा 'वाई' परियोजना में लगा देते थे, तो कभी 'जेड' परियोजना में। नतीजतन कोई भी परियोजना समय से पूरी नहीं हो पाती थी। अमूमन, एजेंट के जरिये वे प्रॉपर्टी की कीमत 50 से 70 फीसदी नकद में वसूलते थे, ताकि काले धन को सफेद बनाया जा सके।

कालांतर में, बड़ी कंपनियां डेवलपर्स बन गईं, जिससे फंड डाइवर्जन, काले धन को सफेद बनाने की प्रक्रिया, खरीदारों को समय पर पजेशन नहीं मिलने जैसी अनियमिताओं पर अंकुश लग गया। सरकार ने भी खरीदारों की परेशानियों को समझा और वर्ष 2016 में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) कानून को अमली-जामा पहनाया।

यह अधिनियम राज्यसभा में 10 मार्च, 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया। रेरा अधिनियम को मूर्त रूप देने का मकसद था घरेलू खरीदारों के हितों की रक्षा करना। यह कानून डेवलपर को परियोजना के दो-तिहाई से अधिक खरीदारों की लिखित सहमति के बिना किसी फ्लैट, मकान, दुकान के लिए स्वीकृत योजना से अलग बदलाव करने से प्रतिबंधित करता है। इस कानून को अमली-जामा पहनाने के बाद से रियल एस्टेट में निवेश करने वाले ईमानदार निवेशकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कुछ राज्यों को छोड़कर, भारत के लगभग सभी राज्यों ने रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए राज्य रेरा कानून को मूर्त रूप दिया। बेशक रेरा कानून रियल एस्टेट कारोबार में पारदर्शिता और जबावदेही लेकर आया, इसके बावजूद, यह रियल एस्टेट एजेंटों के काले कारनामों पर प्रभावी ढंग से लगाम नहीं लगा सका। आज भी रियल एस्टेट एजेंट मोटी कमीशन के लालच में भ्रम पैदा करने वाली सूचनाएं, गलत जानकारी आदि देकर खरीदारों को दोयम दर्जे की प्रॉपर्टी मुंहमांगी कीमत पर दिलवा रहे हैं। अमूमन, खरीदार को अपार्टमेंट के आसपास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे उपलब्ध कराई गई सूचनाओं को न तो स्वयं सत्यापित कर पाते हैं और न ही किसी दूसरे से उसका सत्यापन करवा पाते हैं। अंतत, वे एजेंट के झांसे में आकर ठगे जाते हैं। साफ है कि रियल एस्टेट एजेंट और डेवलपर को तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जब उनकी धोखाधड़ी को साबित किया जा सके। लिहाजा, सरकार को रेरा कानून की तरह रियल एस्टेट एजेंट की जबावदेही तय करने के लिए एक ऐसे कानून को मूर्त रूप देना चाहिए, जिसमें केवल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रियल एस्टेट एजेंट का कार्य करने, रियल एस्टेट एजेंट को डेवलपर का कानूनी प्रतिनिधि बनाने, रियल एस्टेट एजेंट को नियुक्ति पत्र और कमीशन देने की शर्तों का उल्लेख ऑफर लेटर में करने आदि के प्रावधान होने चाहिए।

# छत्तीसगढ़ में विकास का सर्वस्पर्शी मॉडल

## आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन

राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने अयोध्या स्थित भव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की। राज्य में राजिम कुंभ (कल्प) का भव्य आयोजन पुन: शुरू कर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे वैश्विक पहचान दी है। इसी तरह धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में पांच शक्तिपीठों को विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 हजार किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। राज्य की रामायण मंडलियों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के साथ बस्तर दशहरे को 50 लाख, चित्रकोट के लिए 10 लाख की जगह 25 लाख रुपये, रामाराम मेले के लिए 15 लाख रुपये तथा गोंचा पर्व के लिए 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को इसी बात से परखा जा सकता है कि सरकार के गठन के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहली कैबिनेट में विष्णु देव साय सरकार ने 18 लाख 12,743 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया। योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का भी प्रावधान किया गया। वर्तमान में लगभग 15 लाख आवास के निर्माण को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विकास का सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी मॉडल देखने को मिल रहा है।

### भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति

विष्णु देव साय सरकार एक ओर सुशासन की दिशा में नीतिगत कदम उठा रही है, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अमल में ला रही है। पूर्ववर्ती सरकार में हुए पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। साथ ही EWO द्वारा भी इस घोटाले में जांच की जाएगी है। कोयला और शराब घोटाले में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस तरह सरकार भ्रष्टाचार ख़त्म करने का प्रयास कर रही है।

### योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वय पर जोर

सुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। पं.दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय का आधार बताया है। इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया गया है। यह विभाग राज्य में चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन व संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन करेगा। सरकारी योजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा के लिए सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया गया।

### अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का अंत्योदय

पं.दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय का आधार बताया है। इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया गया है। यह विभाग राज्य में चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन व संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन करेगा। सरकारी योजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा के लिए सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया गया।

## विकास के 10 स्तंभों की संकल्पना

विष्णु देव साय सरकार ने अपने पहले बजट में छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक ले जाने का रोडमैप प्रस्तुत किया है। 1 नवंबर 2024 को राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर सरकार के विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करेगी। इसमें 2047 तक छत्तीसगढ़ की तरक्की की कार्ययोजना का विस्तृत वर्णन होगा। राज्य सरकार ने बजट में प्रदेश के अर्थतंत्र को गति देने के दस स्तंभ चिन्हिंत किए हैं।

### अर्थतंत्र को गति देने के दस स्तंभ

1. ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था
2. तकनीक आधारित सुधार व सुशासन
3. आधिकारिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाना
4. प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन
5. सेवा क्षेत्र को बढ़ावा
6. निजी निवेश
7. बस्तर-सरगुजा की ओर देखो नीति
8. डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स का विकास
9. छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रोत्साहन
10. योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन

## विष्णु देव सरकार... 13 दिसंबर को ली शपथ और छत्तीसगढ़ में चल पड़ा विकास का सिलसिला

13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में खुशियों का नया सूर्योदय हुआ। राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट के शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश में विकास का सिलसिला चल पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णयों से विष्णुदेव साय सरकार ने सुशासन को नया आयाम दिया है। किसान, युवा, महिला, गरीब, आदिवासी सहित सभी तबकों तक विकास की बयार पहुंच रही है।

मोदी की गारंटी
सुशासन के तीन माह

## युवा हितैषी सरकार

प्रदेश के युवाओं को शासकीय भर्तियों में निष्पक्ष और पारदर्शिता से युक्त परीक्षा का वातावरण मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इससे भर्ती परीक्षाओं में न सिर्फ युवाओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि परिश्रम से वह अपने सपनों की उड़ान को पूरी कर सकेंगे। सरकार के गठन के पहले महीने में ही विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकमत आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर तथा अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

## आतंकवाद, नक्सलवाद और चरमपंथ पर ठोस प्रहार

छत्तीसगढ़ सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद और चरमंथ को समूल नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर स्टेट इनवेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जा रहा है। यह एजेंसी आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवादी मामलों की प्रभावी और त्वरित जांच करेगी। इसके लिए एसआईए एनआईए के साथ समन्वय स्थापित करने वाली राज्य की नोडल एजेंसी होगी। नक्सल प्रभावित गांव के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए सुदूर नक्सल प्रभावित गांव में 24 योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित गांव में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं। सुकमा के पूवर्ती समेत अन्य स्थानों पर यह पुलिस कैंप कानून व्यवस्था को मजबूती देने के साथ सुशासन के प्रकल्प बनकर उभरे हैं।

## भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।

## डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब राज्य की नवनिर्वाचित सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का पहला डिजिटल बजट पेश किया। इससे शासन एवं प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल अनुप्रयोग के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे। राज्य में कोयले के परिवहन हेतु परमिट और स्वीकृति व्यवस्था मैन्युअल होने से पूर्व की सरकार के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ऐसे में विष्णु देव साय सरकार ने तत्काल इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मिसाल पेश की है। प्रदेश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये, पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपये, एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये और अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

**विगत 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में 'महतारी वंदन योजना' की पहले किस्त की राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने माता- बहनों को शुभकामनाएं दीं।**

## 'महतारी वंदन' योजना से हो रहा महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण विष्णु देव साय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के इतिहास में 12 मार्च 2024 की तारीख महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 1,000 रुपये की पहली किश्त जारी की गई। विष्णु देव साय सरकार हर साल 12 हजार रुपये महिलाओं के खाते में जमा करेगी। भ्रष्टाचार के बिना हितग्राहियों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ डीबीटी का सबसे बेहतरीन उपयोग करने वाला राज्य बन चुका है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंगविभेद, असमानता खत्म करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के साथ ही विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है।

**महतारी वंदन हेल्पलाइन- 0771-2220006 / 0771-6637711**

## किसानों के चेहरे पर खुशी... छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य

छत्तीसगढ़ में धान की फसल यहां के किसानों के लिए तरक्की का आधार है। विष्णु देव साय सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी की मोदी की गारंटी को पूरा कर देश में किसानों को धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य देने का कीर्तिमान रच दिया है। किसानों के खाते में सीधे नगद लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए पैसा भेजा जा रहा है। खरीफ सीजन 2023 में किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ (3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से) 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। इस तरह छत्तीसगढ़ ने देश में धान की खरीदी का रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में 13 लाख किसानों के खाते में धान के दो वर्ष के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कृषक उन्नति योजना के जरिए किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि 13,320 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 24.72 लाख से अधिक किसान विष्णु देव साय सरकार की योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

## "अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047"

विजन डॉक्यूमेंट में राज्य हेतु संभावित विकास क्षेत्रों जैसे कि ईन्फास्ट्रक्चर विकास, कृषि आधुनीकीकरण, शिक्षा व कौशल विकास,GYAN आधारित विकास, निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनों का प्रभावी उपयोग, रिन्यूवेबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, प्रभावी फिस्कल व टैक्स पॉलिसी व तकनीक का उपयोग, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, फूड प्रोसेसिंग मिलेट्स, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास हेतु रणनीति व कार्ययोजना का समावेश होगा। जिसके आधार पर संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

## छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
- डिग्री हासिल करने वाले 246 एमबीबीएस एवं 21 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति दे दी गई है। इनमें से पचास फीसदी की नियुक्ति बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए की गई है।
- स्वास्थ्य विभाग में 5 हजार से ज्यादा पदों पर पीएससी और व्यापम के जरिए भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
- एमबीबीएस एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर नियुक्ति देने की घोषणा की गई है।
- कोल परिवहन के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली - खनिज संसाधन से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य में कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली लागू की गई है।
- नियद नेल्लानार योजना (बस्तर के लिए) बस्तर संभाग के नक्सल पीड़ित क्षेत्र में स्थापित 14 नये कैंपों में नवाचार के रूप में इसके आसपास के 5 ग्रामों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास की कार्यवाही की जाएगी।
- कॉलेज के विद्यार्थियों को 6000 रुपए सालाना ट्रैवल एलाउंस अगले शिक्षा सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को 6000 रुपए सालाना ट्रैवल एलाउंस मिलेगा।
- संस्कृत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का निर्णय शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का संकल्प।
- आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में इसी सत्र से प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी।
- 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी अगले शिक्षा सत्र में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- सभी जिला मुख्यालयों में एम्स की तर्ज पर उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना का निर्णय।

संवाद- 40024/128

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.